Follow Us:- @newsroutine @newsroutine @newsroutine @newsroutine

RNI NO. CHHHIN/2022/83778

न्यूज रूटीन

बढ़ते हुए कदम

E-mail: newsroutine6@gmail.com

✦ वर्ष-05 ✦ अंक-07 ✦ जुलाई-2026 ✦ सारंगढ़-बिलाईगढ़ से प्रकाशित ✦ पृष्ठ-32 ✦ मूल्य-35 रुपये

SECL की खदानों से देश के राजस्व को सरेआम लूटा गया और अफसर इसे 'प्राकृतिक बदलाव' बताते रहे!

ब्लैक डायमंड का 'व्हाइट कॉलर' डाका

336 करोड़ का वो कोयला घोटाला, जिसने पीएमओ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हड़कंप मचा दिया!

तेन्दूपत्ता संग्राहकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध

रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार ने 7.14 लाख से अधिक तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 162.32 करोड़ की प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) राशि का वितरण किया है। राज्य में वर्तमान में तेन्दूपत्ता संग्रहण की दर को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा किया गया है, जिससे संग्राहक परिवारों को सीधा आर्थिक संबल मिल रहा है। तेन्दूपत्ता का संग्रहण दर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा होने से संग्राहक परिवारों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार तेन्दूपत्ता संग्राहकों, वनवासियों और आदिवासी परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगल से जुड़े प्रत्येक श्रमिक को उसके श्रम का उचित सम्मान मिले और पारिश्रमिक समय पर सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचे। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने बताया कि विगत 3 जुलाई को सहकारिता सप्ताह एवं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा वर्ष 2023 के तेन्दूपत्ता संग्रहण के प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण का शुभारंभ किया गया। इसके तहत प्रदेश की 621 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों से जुड़े 7,14,446 तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 162.32 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। भुगतान की प्रक्रिया तेजी से जारी है और शीघ्र पूरी कर ली जाएगी।

वन मंत्री ने बताया कि सरकार ने संग्रहण सत्र 2026 में भी तेन्दूपत्ता संग्राहकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया है। प्रदेश के लगभग 11.15 लाख संग्राहकों को 734.25 करोड़ रुपए की संग्रहण पारिश्रमिक राशि ऑनलाइन माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। इससे लाखों वनवासी और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक मजबूती मिली है। श्री केदार कश्यप ने कहा कि तेन्दूपत्ता प्रदेश के लाखों वनवासी परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार है। इसलिए राज्य सरकार संग्रहण से लेकर भुगतान तक पूरी व्यवस्था को पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बना रही है, ताकि संग्राहकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को समय पर पारिश्रमिक और प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना इसी सोच का परिणाम है। आने वाले समय में भी सरकार वनवासियों के हितों की रक्षा, उनकी आय में वृद्धि तथा वन आधारित आजीविका को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।

न्यूज रूटीन

बढ़ते हुए कदम

RNI NO. CHHHIN/2022/83778
E-mail: newsroutine6@gmail.com

सारंगढ़-बिलाईगढ़ से प्रकाशित

प्रधान संपादक
गुलाब दास दीवान

सह- संपादक
जयदास मानिकपुरी

कानूनी सलाहकार
जवाहर पड़वार
इंदुभूषण पड़वार

प्रधान कार्यालय
न्यूज रूटीन
बाजार काम्पलेक्स, नगर पंचायत
पवनी, जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़
पिन. नं. 493338
मो.नं. 9294743139

रायपुर कार्यालय
सह- संपादक-**जयदास मानिकपुरी**
देव मेडिकल स्टोर के पास,हाउस नम्बर
55वार्ड नंबर- 04, साई राम चौक,
गोवर्धन नगर भनपुरी, रायपुर
मो. न. 62611,55546 छत्तीसगढ़- 492001

न्यूज रूटीन में प्रकाशित आलेखों से संपादक, प्रकाशक, मुदक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। विवादग्रस्त न्यायिक प्रकरणों का कार्यक्षेत्र सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला रहेगा। सभी पद पूर्णतः मानसेवी व अवैतनिक। समाचार स्त्रोत हमारे सभी संवाददाता/प्रतिनिधि। संदर्भ सामग्रीः इंटरनेट, प्रमुख समाचार पत्र एवं नामचीन पत्रिकाओं से सादर साभार।
संपादक- गुलाब दास दीवान

वर्ष-05 | अंक- 07 | जुलाई-2026

इस अंक में

2. राम मंदिर चढ़ावा चोरी को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना पाएगी
3. सुशासन, विकास और जनकल्याण ही हमारी सरकार ...
6. जहां विकास के पहिए दौड़ने चाहिए थे, वहां आज गड्ढों में जिंदगी फंस रही है
7. खेत में बुजुर्ग किसान की नृशंस हत्या से दहला पूरा ..
8. बलौदाबाजार में बकाया राशि नहीं लौटाने वाले 5 पूर्व ..
9. शिक्षा के मंदिर में 'रिश्वत का खेल' ?
11. सारंगढ़ की फाइलों को मिली नई रफ्तार
12. बेमेतरा से बालोद पहुंचे बेटा-बेटी, मां को सही-सलामत ..
13. 29 पेड़ों की अवैध कटाई पर बड़भूम स्कूल के प्रधान ...
14. करोड़ों की सड़क या भ्रष्टाचार का रास्ता
15. स्कूले खुले लेकिन किताबें गायब
16. धमतरी में बड़ा एक्शन फर्जी दस्तावेज पर नौकरी पाने
17. एक शिकायत से हिलाई पंचायत व्यवस्था
18. लोककला की अमर स्वर-सरिता को राजकीय सम्मान
19. पंडवानी की अमर स्वर-गाथाः तीजन बाई को सांगीतिक
20. छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास को मिल रही अभूतपूर्व ...

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक- **गुलाब दास दीवान,** द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. (छ.ग.) भवन, प्रेस काम्पलेक्स रजबंधा मैदान रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं ग्राम-पोस्ट-पवनी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला (छ.ग.), 493338 से प्रकाशित।
RNI NO. CHHHIN/2022/83778 सम्पादक गुलाब दास दीवान, मो. 9294743139

राम मंदिर चढ़ावा चोरी को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना पाएगी

राजनीति में मुद्दे सामने आते रहते हैं,कई मुद्दे अपने आप में बड़े होते हैं,कई मुद्दे बड़े नहीं होते हैं, उनको बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास राजनीतिक दल करते हैं लेकिन राजनीतिक दल किसी मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने में सफल हुए या नहीं, इस बात का पता तो चुनाव में चलता है चाहे वह किसी राज्य का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो।विपक्ष में कांग्रेस ही सबसे पुरानी व बड़ा राजनीतिक पार्टी है।कुछ राज्यों में उसकी सरकार है और कई राज्यों में वह भाजपा का विकल्प है।उसके नेता राहुल गांधी तो हर मुद्दे को बड़ा मुद्दा बताते हैं लेकिन उनकी कमजोरी या विशेषता यही है कि वह किसी मुद्दे को बड़ा नहीं बना पाते हैं। वह कहते हैं बड़ा मुद्दा है, बड़ा घोटाला है,देश के लोग नाराज है,जनता में नाराजगी है,यह सरकार एक साल में गिर जाएगी लेकिन जब भी चुनाव होता है तो पता चलता है कि कांग्रेस जिसे बड़ा मुद्दा समझ रही थी,जनता तो उसे बड़ा मुद्दा नहीं मानती है।जनता कांग्रेस की तुलना में भाजपा पर ही ज्यादा भरोसा करती है।जनता केंद्र हो या राज्य हो सत्ता भाजपा को ही सौंप देती है। राहुल गांधी का पिछले कुछ सालों में सबसे प्रिय विषय है चोरी।उनको लगता है कि हर जगह चोरी हो रही है।कहीं वोट चोरी हो रही है तो कहीं सीट चोरी हो रही है,भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर चोरी कर रहे हैं और कांग्रेस देख रही है और रोक नहीं पा रही है।राहुल गांधी जब कहते हैं कि वोट चोरी कर सरकार बना रहे हैं तो जनता के मन में सवाल आता है कि उसे रोकना तो कांग्रेस का काम है, वह रोक क्यों नहीं पाती है, वह हल्ला भर करती है। हल्ला करने से तो चोरी रुकती नहीं है,चोरी नहीं रुकेगी तो कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी।कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तो चोरी को रोकना होगा। यही काम कांग्रेस करती नहीं है तो जनता उसके हल्ला करने को गंभीरता से नहीं लेती है।अब अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी या दान चोरी का मामला सामने आया है तो कांग्रेस को लग रहा है कि वह इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है। भाजपा को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है,चुनाव में इसका फायदा उठा सकती है। यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्यों के स्तर पर कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है।छत्तीसगढ़ मे भी इसे बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास करते हुए विधानसभा में इस पर चर्चा कराने का प्रयास कांग्रेस ने किया।कांग्रेस ने इस मामले में छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से उठा। कांग्रेस ने इस मामले पर चर्चा की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया।नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी के मामले में छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ रामभक्तों की आस्था आहत हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए दान दिया है, इसलिए इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। ।पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग दिया था। यदि उन पैसों में कथित अनियमितता या चोरी की बात सामने आई है तो इस पर चर्चा होना स्वाभाविक है। लंबी बहस के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने स्पष्ट किया कि यह मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इसे राज्य का विषय नहीं मानते हुए कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया गया। यह सच है कि राज्य के लोगों ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया है। उस चंदे से राममंदिर बना है, पर सचाई यह है कि राम मंदिर के लिए दिए गए चंदे की कोई चोरी नहीं हुई. चोरी तो चढ़ावे की हुई है। इससे लोगों को बुरा लगा है। क्योंकि राम के प्रति इस देश में इतनी आस्था है कि कोई सोच नहीं सकता था कि राम के नाम पर दिए गए दान को भी कोई चुरा सकता है।लोगों में गुस्सा है कि राममंदिर में दूसरे बड़े मंदिरों की तरह ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई कि कोई चढ़ावे में चोरी कर सके। हो सकता है यह चूक इस अतिविश्वास के कारण हुई हो कि राममंदिर में कोई दान की चोरी नहीं करेगा।जिस ट्रस्ट पर भरोसा किया गया उस ट्रस्ट के कुछ लोग भरोसे का बनाए नहीं रख सके। इसका नुकसान भाजपा को हो सकता है,यह भाजपा जानती है,इसलिए विपक्ष उसको नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है तो वह भी नुकसान कम करने का न हो इसके लिए कोशिश तो कर रहा है। यह सच है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से लोग नाराज है,विपक्ष सोच रहा है कि जनता की नाराजगी को बढ़ाकर वह भाजपा को यूपी व देश में राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है।क्या जनता भी ऐसा सोच रही है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होने की सजा यूपी में भाजपा को हराने के रूप में दी जाए। योगी सरकार यही काम करने का प्रयास कर रही है कि चोरी करने वालों को सजा मिले और भविष्य मे चोरी न हो।कांग्रेस एक बात समझ नहीं पा रही है कि राम मंदिर अब राजनीति का मुद्दा नही रह गया है। उससे न तो कोई लाभ होना है न ही कोई हानि होनी है। राममंदिर आस्था का मुद्दा है और राम के प्रति कांग्रेस भाजपा से ज्यादा आस्थावान नहीं है।

गुलाब दास दीवान

सुशासन, विकास और जनकल्याण ही हमारी सरकार की पहचान है : मुख्यमंत्री साय

न्यूज रुटीन @ रायपुर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज आरंग विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत समोदा में आयोजित कार्यक्रम में 128 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के विकास को नई गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्राम पंचायत रीवा में लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉप डैम निर्माण, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समोदा में अहाता निर्माण, नगर पंचायत समोदा के पंचायत भवन में प्रथम तल निर्माण तथा ग्राम तुलसी के हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी विद्यालय में उन्नयन की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन, विकास और जनकल्याण ही हमारी सरकार की पहचान है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि ₹मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी₹ केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार की कार्यशैली और जनविश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने 18 लाख गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 10 लाख से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं। किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है तथा महतारी वंदन योजना के

अंतर्गत अब तक 28 किश्तों में 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी सोच के साथ बस्तर सहित प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही आधारित प्रशासन स्थापित करने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार और अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के साथ नागरिक सेवाओं को अधिक सरल और सुलभ बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद, बीज एवं कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। नागरिकों की सुविधा के लिए सेवा सेतु के माध्यम से 520 से अधिक शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के जरिए शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सहकारिता, महिला सशक्तिकरण और जनकल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। उन्होंने नागरिकों से शासन की योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने का आग्रह करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि तीन माह के लिए बढ़ा दी गई है। पात्र उपभोक्ता ₹मोर बिजली₹ मोबाइल एप अथवा वेबसाइट के माध्यम से सितंबर तक पंजीयन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। कार्यक्रम में कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आरंग विधानसभा क्षेत्र को अब तक 858 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास और सुशासन की नई दिशा स्थापित हुई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' अभियान के अंतर्गत आंवला का पौधारोपण किया। उन्होंने सरस्वती साइकिल योजना के तहत कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरित की तथा जिला प्रशासन के मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित किया।इस अवसर पर छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री ध्रुव कुमार मिर्धा, छत्तीसगढ़ औषधीय पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री अंजय शुक्ला, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

ब्लैक डायमंड का 'व्हाइट कॉलर' डाका

336 करोड़ का वो कोयला घोटाला, जिसने पीएमओ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हड़कंप मचा दिया!

विशेष खोजी रिपोर्ट

नई दिल्ली / बिलासपुर / कोरबाः

क्या भारत सरकार के खजाने में इतनी बड़ी सेंध लगाई जा सकती है कि शीर्ष पर बैठे लोग उसे 'कुदरत का करिश्मा' बताकर फाइलें बंद कर दें? कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी South Eastern Coalfields Limited के गलियारों से उठ रही घोटाले की यह गूंज अब देश के नीति-निर्धारकों और जन-प्रतिनिधियों के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। एक आरटीआई कार्यकर्ता और पत्रकार जितेंद्र कुमार साहू के पास मौजूद पुख्ता दस्तावेजों ने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय , सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के दरवाजों पर दस्तक दे दी है। मामला सीधे तौर पर 3,36,78,21,990.88 (3 अरब 36 करोड़ से अधिक) के संगठित वित्तीय अपराध और देश के राजस्व की खुली डकैती का है।

- **घोटाले का 'क्रोनोलॉजी':** ऐसे बदला जाता है कोयले का रंग और दाम शिकायत और आधिकारिक वित्तीय रिकॉर्ड (पत्र क्र. 155, दिनांक 12/08/2025) के मुताबिक, यह पूरा खेल एक बेहद शातिर सिंडिकेट के जरिए खेला जा रहा हैः
- **कागजों पर 'सुपर क्वालिटी':** SECL कोरबा क्षेत्र की खदानों से जब रेलवे और सड़क मार्ग से कोयला भेजा जाता है, तो दस्तावेजों में उसे उच्च ग्रेड जैसे G4 और G5 दिखाया जाता है। इसके आधार पर भारी-भरकम बिल जनरेट होते हैं।
- **'थर्ड पार्टी' की एंट्री और जादूगरीः** कोयला रवाना होने के बाद, 'थर्ड पार्टी सैंपल कलेक्शन एजेंसियों' के साथ मिलकर एक कथित खेल होता है। लैब टेस्टिंग में अचानक कोयले की गुणवत्ता को भारी रूप से गिरा हुआ घोषित कर दिया जाता है।
- **अरबों का रिफंडः** गुणवत्ता गिरने के नाम पर क्रेडिट नोट्स जारी किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 के बीच, कुल 3,36,78,21,990.88 की शुद्ध राशि बिलासपुर मुख्यालय स्तर से प्रोसेस करके चुनिंदा निजी घरानों को वापस (रिफंड) लौटा दी गई!
- **बड़ा सवालः** जब कोयला खदान से उच्च ग्रेड का निकला, तो रास्ते में या लैब में पहुंचते ही वह 'मिट्टी' कैसे बन गया? और अगर गुणवत्ता खराब थी, तो लगातार 7 सालों तक एक ही गलती करके निजी कंपनियों को ही फायदा क्यों पहुंचाया गया?

अधिकारियों का अजब तर्कः ₹कोयला खुद गर्म होकर अपनी क्वालिटी खराब कर लेता है!

जब इस महाघोटाले की शिकायत CPGRAMS (शिकायत क्रमांकः PMOPG/D/2026/0095647) के जरिए प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची, तो SECL प्रबंधन के बचाव ने सबको चौंका दिया। Area Quality Manager, कोरबा ने 1 जून 2026 को एक तकनीकी प्रतिवेदन जारी कर इस अरबों के वित्तीय नुकसान को 'स्वाभाविक और प्राकृतिक' करार दे दिया।

प्रबंधन के मुताबिक

- खदानों में पत्थरों के टुकड़े और भू-वैज्ञानिक परिस्थितियां ग्रेड बदलने के लिए जिम्मेदार हैं।

7 साल, 3.36 अरब का रिफंड और 'थर्ड पार्टी' का वो खेल... जानिए कैसे SECL की खदानों से देश के राजस्व को सरेआम लूटा गया और अफसर इसे 'प्राकृतिक बदलाव' बताते रहे!

- कोयले में खुद गर्म होने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, जिससे उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है।
- केवल क्रेडिट नोट जारी होना किसी वित्तीय अपराध का प्रमाण नहीं है।

सवालों के घेरे में 'क्वालिटी मैनेजर' की भूमिका

- आवेदक ने 9 जुलाई 2026 को इस तकनीकी रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे बिलासपुर मुख्यालय और दागी अफसरों को बचाने की एक 'दुर्भावनापूर्ण कोशिश' करार दिया है। सवाल यह है कि यदि यह एक तकनीकी समस्या थी, तो पिछले 7 वर्षों में खदानों की ग्रेडिंग सुधारने या देश का वित्तीय नुकसान रोकने के लिए Area Quality Manager द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए? क्या पूरी जिम्मेदारी सिर्फ थर्ड पार्टी एजेंसी पर डालकर अधिकारी अपनी वैधानिक जिम्मेदारी से बच सकते हैं?

पारदर्शिता की धज्जियां आरटीआई पर 'सेंसरशिप'

- इस महाघोटाले की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरटीआई के तहत मांगी जा रही वित्तीय जानकारियों को जानबूझकर छुपाया जा रहा है। केंद्रीय सूचना आयोग को गुमराह करने और पारदर्शिता अधिनियम की धज्जियां उड़ाने के भी गंभीर आरोप मुख्यालय के शीर्ष अधिकारियों पर लगे हैं।

क्या हिलेगी दिल्ली? इन 3 मांगों पर टिकी हैं देश की नजरें

- शिकायतकर्ता ने सीधे भारत के प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और केंद्रीय जांच एजेंसियों को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की हैः
- CBI-ED की तत्काल एफआईआरः मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत SECL बिलासपुर मुख्यालय के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , तकनीकी निदेशक और कोरबा क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए।
- फॉरेंसिक ऑडिटः पिछले 7 वर्षों में जारी किए गए सभी क्रेडिट नोट्स, रिफंड फाइलों और थर्ड पार्टी सैंपलिंग की रिपोर्ट का एक स्वतंत्र विशेष फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए।
- **न्यायिक संज्ञानः** सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर देश के राजस्व की इस खुली डकैती पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अपनी निगरानी में समयबद्ध जांच सुनिश्चित करें।
- यह सिर्फ कोयले की ग्रेडिंग का तकनीकी हेरफेर नहीं है, बल्कि देश के खजाने में सीधे तौर पर लगाई गई 3.36 अरब की सेंधमारी का स्थापित सिंडिकेट दिखाई देता है। यदि देश के जन-प्रतिनिधि और केंद्रीय एजेंसियां अब भी खामोश रहीं, तो ₹जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन₹ का नारा महज एक कागजी दावा बनकर रह जाएगा। अब देखना यह है कि क्या देश के सर्वोच्च संस्थान इस खुली डकैती पर कड़ा प्रहार करते हैं या 'कोयले की दलाली' में सच को ऐसे ही दफन कर दिया जाएगा।

जहां विकास के पहिए दौड़ने चाहिए थे, वहां आज गड्ढों में जिंदगी फंस रही है

लगातार बारिश ने खोली बदहाल सड़क की पोल, गहरे गड्ढों और कीचड़ के बीच जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं हजारों लोग

रिपोर्ट : विशेष संवाददाता

रायगढ़ जिले की गेरवानी-सराईपाली सड़क आज विकास के सरकारी दावों पर सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ी है। कभी औद्योगिक विकास की रीढ़ मानी जाने वाली यह सड़क अब बदहाली, लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता की पहचान बन चुकी है। बारिश शुरू होते ही सड़क पर बने गहरे गड्ढे, जलभराव और कीचड़ इस मार्ग को किसी भी समय जानलेवा साबित कर सकते हैं। हर दिन सैकड़ों ट्रेलर, हाईवा, मालवाहक वाहन, उद्योगों के कर्मचारी, स्कूली छात्र, व्यापारी और ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर इस सड़क से गुजरने को मजबूर हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक विकास की कीमत लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर चुकानी पड़ेगी?

सड़क नहीं, हादसों का गलियारा

लगातार बारिश ने गेरवानी-सराईपाली सड़क की वास्तविक तस्वीर सामने ला दी है। जगह-जगह डामर पूरी तरह उखड़ चुका है और सड़क गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई है। अधिकांश गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। वाहन चालक अचानक गड्ढों में उतर जाते हैं, जिससे वाहन अनियंत्रित हो जाते हैं और दुर्घटना की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। दोपहिया वाहन चालकों की स्थिति सबसे अधिक खराब है। हल्की-सी चूक उन्हें गंभीर हादसे का शिकार बना सकती है। बारिश के दौरान फिसलन और भारी वाहनों के दबाव के बीच छोटे वाहन चालक खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस सड़क पर कई बार बड़े हादसे होते-होते बचे हैं, जबकि पूर्व में कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं।

उद्योगों की लाइफलाइन, लेकिन बदहाली चरम पर

गेरवानी-सराईपाली मार्ग केवल एक सामान्य सड़क नहीं है। यह रायगढ़ जिले के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। प्रतिदिन इस सड़क से सैकड़ों ट्रेलर, हाईवा, डंपर और अन्य भारी वाहन गुजरते हैं। उद्योगों में कार्यरत हजारों कर्मचारी, स्थानीय व्यापारी और आसपास के गांवों के लोग भी इसी मार्ग पर निर्भर हैं।

विडंबना यह है कि जिस सड़क के सहारे करोड़ों रुपये का औद्योगिक कारोबार संचालित होता है, उसी सड़क की मरम्मत और चौड़ीकरण वर्षों से उपेक्षित है। लगातार भारी वाहनों की आवाजाही ने सड़क की स्थिति को और अधिक खराब कर दिया है। जहां गुणव-त्तापूर्ण निर्माण और नियमित रखरखाव की

प्रशासन की अनदेखी या जनता की मजबूरी? गेरवानी-सराईपाली सड़क पर बड़ा सवाल

आवश्यकता थी, वहां लोगों को बदहाल सड़क और टूटे हुए डामर से समझौता करना पड़ रहा है।

बारिश आते ही बढ़ जाती है परेशानी

मानसून इस सड़क के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होता। हल्की बारिश के बाद ही सड़क की परत उखड़ने लगती है और गड्ढे तेजी से बड़े होते जाते हैं। कई स्थानों पर पानी भर जाने से सड़क और गड्ढे में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वाहन चालकों को बेहद धीमी गति से सफर करना पड़ता है। यात्रा का समय बढ़ जाता है, ईंधन की खपत बढ़ती है और वाहन भी लगातार खराब होते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में कई बार एंबुलेंस और जरूरी सेवाओं के वाहनों को भी इस मार्ग से गुजरने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

वर्षों से उठ रही मांग, लेकिन समाधान नहीं

स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और वाहन चालकों का कहना है कि गेरवानी-सराईपाली सड़क के चौड़ीकरण और स्थायी मरम्मत की मांग लंबे समय से की जा रही है। कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस और स्थायी पहल दिखाई नहीं दी। लोगों का कहना है कि हर वर्ष बारिश के बाद अस्थायी मरम्मत कर दी जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में सड़क फिर पहले जैसी हो जाती है। इससे सरकारी धन भी खर्च होता है और जनता की परेशानी भी खत्म नहीं होती।

आर्थिक गतिविधियों पर भी असर

यह सड़क केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों की धुरी भी है। सड़क की खराब स्थिति के कारण माल परिवहन प्रभावित होता है, उद्योगों की लॉजिस्टिक लागत बढ़ती है और स्थानीय व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। कई वाहन चालक इस मार्ग से गुजरने से बचने के लिए लंबा रास्ता अपनाते हैं, जिससे समय और ईंधन दोनों की अतिरिक्त खपत होती है।

जनता का सवाल

आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या लोगों की जान की कीमत सड़क निर्माण से भी कम है? आखिर ऐसी महत्वपूर्ण सड़क वर्षों तक बदहाल क्यों बनी हुई है? यदि यह औद्योगिक क्षेत्र की जीवनरेखा है, तो इसकी अनदेखी आखिर किसकी जिम्मेदारी है?

स्थायी समाधान की मांग

स्थानीय लोगों की मांग है कि गेरवानी-सराईपाली सड़क की केवल खानापूर्ति वाली मरम्मत नहीं, बल्कि आधुनिक मानकों के अनुरूप चौड़ीकरण और गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण कराया जाए। साथ ही जल निकासी की समुचित व्यवस्था, नियमित रखरखाव और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की स्वतंत्र निगरानी भी सुनिश्चित की जाए। गेरवानी-सराईपाली सड़क आज केवल एक सड़क की कहानी नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का आईना है जहां विकास के दावों के बीच आम नागरिक अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह बदहाल सड़क किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। सवाल यही है—क्या प्रशासन चेतावनी को समझेगा, या फिर किसी बड़ी त्रासदी का इंतजार करेगा?

खेत में बुजुर्ग किसान की नृशंस हत्या से दहला पूरा जुनवानी गांव

सारंगढ़ः- सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के भटगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत जुनवानी में एक बुजुर्ग किसान की नृशंस हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। गांव के शांत माहौल के बीच हुई इस वारदात ने ग्रामीणों को स्तब्ध कर दिया है। ग्राम जुनवानी निवासी तुलसी दास टंडन उम्र 70 वर्ष शुक्रवार 10 जुलाई की सुबह अपने दैनिक कार्य के अनुसार खेती किसानी के लिए खेत गए थे। परिवार के लोगों को उम्मीद थी की वे रोज की तरह शाम तक घर लौट आएंगे, लेकिन देर शाम तक उनके घर नहीं पहुंचने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई। तब परिजनों ने पहले आसपास के खेतों और परिचितों के यहां उनकी तलाश की। जब काफी देर तक उनका कोई पता नहीं चला तो गांव के लोगों को सूचना दी गई। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण टार्च और अन्य साधनों के साथ खेतों एवं आसपास के इलाकों में उनकी खोजबीन में जुट गए। रात लगभग 7 बजे खेत के समीप उनका शव खून से लथपथ अवस्था में मिला। शव की स्थिति देखकर मौके पर मौजूद लोगो के होश उड़ गए और पूरे गांव में शोक तथा दहशत का माहौल फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंच गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक के शरीर पर किसी भारी और धारदार कृषि औजार से क ई गंभीर वार किए गए थे। शरीर पर अनेक गहरे घाव पाए गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना तत्काल भटगांव थाना पुलिस को दी गई, जहां सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल को अपने कब्जे में लेकर आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी की। वहीं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विजय ठाकुर ने स्वयं घटना स्थल का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। और साक्ष्यो के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए घटना स्थल को पूरी रात सुरक्षित रखा गया। ताकि किसी भी महत्वपूर्ण साक्ष्यो से छेड़छाड़ न हो। जहां शनिवार सुबह डांग स्क्वाड, फोरेंसिक विशेषज्ञों तथा अन्य पुलिस अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। और घटना स्थल का बारीकी से निरिक्षण किया गया और वैज्ञानिक तरिके से विभिन्न साक्ष्य एकत्र किए गए।

बलौदाबाजार में बकाया राशि नहीं लौटाने वाले 5 पूर्व सरपंचों पर सख्ती

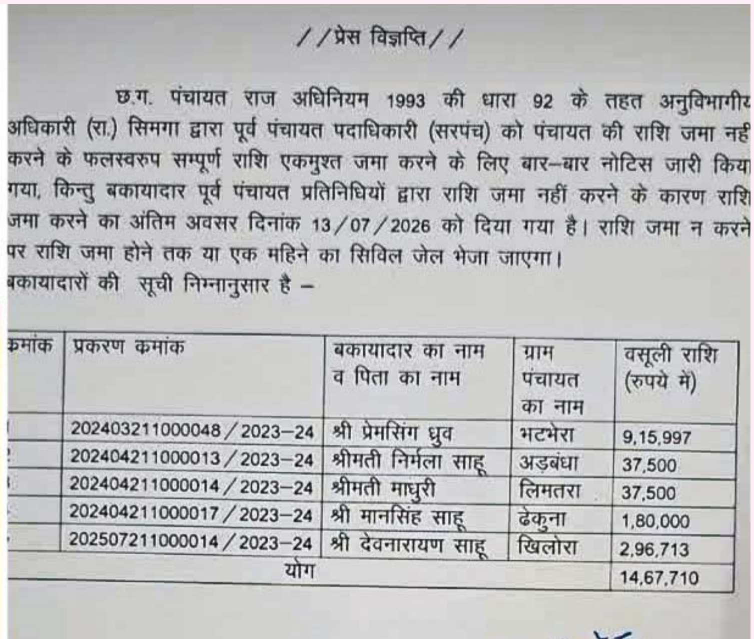

//प्रेस विज्ञप्ति//

छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सिमगा द्वारा पूर्व पंचायत पदाधिकारी (सरपंच) को पंचायत की राशि जमा नहीं करने के फलस्वरुप सम्पूर्ण राशि एकमुश्त जमा करने के लिए बार-बार नोटिस जारी किया गया, किन्तु बकायादार पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा राशि जमा नहीं करने के कारण राशि जमा करने का अंतिम अवसर दिनांक 13/07/2026 को दिया गया है। राशि जमा न करने पर राशि जमा होने तक या एक महिने का सिविल जेल भेजा जाएगा।

बकायादारों की सूची निम्नानुसार है –

क्रमांक	प्रकरण क्रमांक	बकायादार का नाम व पिता का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वसूली राशि (रुपये में)
	202403211000048/2023–24	श्री प्रेमसिंग ध्रुव	भटभेरा	9,15,997
	202404211000013/2023–24	श्रीमती निर्मला साहू	अड़बंधा	37,500
	202404211000014/2023–24	श्रीमती माधुरी	लिमतरा	37,500
	202404211000017/2023–24	श्री मानसिंह साहू	ढेकुना	1,80,000
	202507211000014/2023–24	श्री देवनारायण साहू	खिलोरा	2,96,713
योग				14,67,710

न्यूज रुटीन @ बलौदाबाजार

जिले में शासकीय राशि की वसूली को लेकर जिला प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है. पंचायत की राशि जमा नहीं करने वाले पांच पूर्व सरपंचों को अंतिम चेतावनी नोटिस जारी किया गया है.

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि निर्धारित समय सीमा में बकाया राशि जमा नहीं की गई तो संबंधित पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मामला सिमगा अनुविभाग का है, जहां एसडीएम कार्यालय द्वारा पांच पूर्व सरपंचों से कुल 14 लाख 67 हजार रुपए से अधिक की राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू की गई है.

बार-बार नोटिस के बाद भी जमा नहीं की राशि-एसडीएम सिमगा अतुल शेट्टे ने बताया कि संबंधित पूर्व सरपंचों को पहले भी कई बार नोटिस जारी कर पंचायत की बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद राशि जमा नहीं किए जाने पर अब अंतिम अवसर दिया गया है. प्रशासन ने राशि जमा करने के लिए 13 जुलाई 2026 तक का समय निर्धारित किया है. अगर तय समय तक राशि जमा नहीं की जाती है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

पंचायत राज अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई-प्रशासन ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत की है. इस प्रावधान के अनुसार पंचायत की राशि जमा नहीं करने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों से शासकीय राशि की वसूली की जा सकती है. एसडीएम ने बताया कि राशि जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित पूर्व सरपंचों को राशि जमा होने तक या अधिकतम एक महीने के लिए सिविल जेल भेजने की कार्रवाई भी की जा सकती है.

इन 5 पूर्व सरपंचों को मिला अंतिम नोटिस

- प्रेम सिंह ध्रुव, ग्राम भटभेरा, बकाया राशि- 9 लाख 15 हजार 997 रुपए
- निर्मला साहू, ग्राम अड़बांधा, बकाया राशि- 37 हजार 500 रुपए
- माधुरी, ग्राम लिमतरा, बकाया राशि- 37 हजार 500 रुपए
- मानसिंह साहू, ग्राम ढेकुना, बकाया राशि- 1 लाख 80 हजार रुपए
- देवनारायण साहू, ग्राम खिलोरा, बकाया राशि- 2 लाख 96 हजार 713 रुपए

प्रशासन का सख्त संदेश

पंचायतों में सरकारी राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है.

अधिकारियों का कहना है कि पंचायत निधि जनता के विकास कार्यों के लिए होती है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि पूर्व पंचायत प्रतिनिधि निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.

ग्रामीण विकास से जुड़ी राशि की वसूली

पंचायतों को मिलने वाली राशि का उपयोग सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता और अन्य विकास कार्यों में किया जाता है. ऐसे में राशि का हिसाब-किताब और उसकी जिम्मेदारी तय करना प्रशासन की प्राथमिकता है. अधिकारियों का कहना है कि सरकारी धन की सुरक्षा और जवाबदेही तय करने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक है.

माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए कथित ₹1500 की मांग, कलेक्टर तक पहुंची शिकायत

आत्मानंद स्कूल में कथित रिश्वतखोरी की शिकायत से हड़कंप

गरीब छात्रों से कथित घूस मांगने के आरोपों ने खड़े किए बड़े सवाल

माइग्रेशन सर्टिफिकेट के नाम पर ₹1500 की कथित वसूली से घिरा आत्मानंद स्कूल

शिक्षा के मंदिर में 'रिश्वत का खेल'?

न्यूज रूटीन @ सारंगढ़-बिलाईगढ़

प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएम श्री स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की स्थापना की थी। इस योजना को शिक्षा सुधार की महत्वपूर्ण पहल माना जाता है। लेकिन सारंगढ़ स्थित आत्मानंद विद्यालय से जुड़ा एक मामला अब कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। विद्यालय में पदस्थ हिंदी व्याख्याता बसंत दुबे के विरुद्ध जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ओपन स्कूल के विद्यार्थियों से माइग्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के नाम पर कथित रूप से 1500 की राशि मांगी। शिकायत में यह भी आरोप है कि उन्होंने स्वयं को प्रभारी बताकर विद्यार्थियों और पालकों से संपर्क किया तथा कथित रूप से निजी बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान कराने के लिए कहा। शिकायत सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है।

'माइग्रेशन चाहिए तो ₹1500 दो' शिकायत में क्या कहा गया है?

शिकायत के अनुसार कई विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से कहा गया कि पुराने माइग्रेशन दस्तावेज रायपुर से मंगाने पड़ते हैं और इसके लिए 1500 जमा करना होगा। आरोप है कि यह राशि किसी सरकारी प्रक्रिया के तहत नहीं, बल्कि निजी मोबाइल नंबर के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी कथित कॉल रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन लेन-देन संबंधी जानकारी और अन्य दस्तावेज भी प्रशासन को उपलब्ध कराए गए हैं। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई है।

क्या गरीब छात्रों के भविष्य की भी कीमत तय होगी?

ओपन स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण, गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों से आते हैं। उच्च शिक्षा और कॉलेज प्रवेश के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य दस्तावेज माना जाता है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विद्यार्थियों से कहा जाता था कि यदि निर्धारित राशि नहीं दी गई तो

प्रमाणपत्र मिलने में कठिनाई होगी। यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं, तो सवाल केवल 1500 का नहीं, बल्कि उन परिवारों की मजबूरी का है जो दिनभर मेहनत-मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के भविष्य पर भी कथित आर्थिक दबाव डाला जा सकता है? यह प्रश्न पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पहलू बनकर सामने आया है।

आत्मानंद योजना की साख पर सवाल

स्वामी आत्मानंद विद्यालय योजना का उद्देश्य प्रदेश के विद्यार्थियों को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और समान अवसर वाली शिक्षा उपलब्ध कराना है। लेकिन यदि किसी सरकारी विद्यालय में प्रमाणपत्र जैसी आवश्यक प्रक्रिया के नाम पर अवैध राशि मांगने के आरोप सामने आते हैं, तो इसका सीधा असर योजना की विश्वसनीयता पर पड़ता है। यह मामला केवल एक विद्यालय तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि यह प्रशासनिक निगरानी, जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

प्रभारी कौन? शिकायत का सबसे गंभीर पहलू

शिकायत में दावा किया गया है कि ओपन स्कूल के अधिकृत प्रभारी प्रकाश जायसवाल हैं। इसके बावजूद आरोप लगाया गया है कि बसंत दुबे स्वयं को प्रभारी बताकर विद्यार्थियों और अभिभावकों से संपर्क कर रहे थे तथा प्रमाणपत्र संबंधी प्रक्रिया अपने स्तर पर संचालित कर रहे थे। यदि जांच में यह तथ्य सही पाया जाता है, तो मामला केवल कथित आर्थिक अनियमितता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रशासनिक अधिकारों के कथित दुरुपयोग और सेवा आचरण के उल्लंघन का भी विषय बन सकता है।

क्या छात्रों की मजबूरी बनी कमाई का जरिया?

माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बिना उच्च शिक्षा और कॉलेज प्रवेश की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इसी आवश्यकता का लाभ उठाकर विद्यार्थियों से कथित रूप से राशि मांगी गई। यदि जांच में यह आरोप प्रमाणित होते हैं, तो यह गरीब विद्यार्थियों की विवशता का अनुचित लाभ उठाने जैसा गंभीर मामला माना जाएगा।

शिकायत के साथ सौंपे गए कथित साक्ष्य

पत्रकार संतोष कुमार चौहान ने 6 जुलाई 2026 को जिला कलेक्टर कार्यालय में लिखित शिकायत प्रस्तुत कर मामले की जांच की मांग की है। शिकायत में कथित कॉल रिकॉर्डिंग, दस्तावेज और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए।

प्रशासन से प्रमुख मांगें

- **पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।**
- **यदि आरोप सही पाए जाएं तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए।**
- **माइग्रेशन सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए।**
- **यदि किसी अन्य कर्मचारी या अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए।**

सबसे बड़ा सवाल—क्या जांच सच्चाई सामने लाएगी?

पूरा मामला अब कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यदि वास्तविक प्रभारी कोई अन्य थे, तो प्रमाणपत्र संबंधी प्रक्रिया कथित रूप से किसी दूसरे कर्मचारी द्वारा किस आधार पर संचालित की जा रही थी? निजी खाते में राशि लेने के आरोपों की सच्चाई क्या है? क्या यह एक व्यक्ति तक सीमित मामला है या प्रशासनिक व्यवस्था की किसी बड़ी खामी का संकेत?

इन सभी प्रश्नों का उत्तर अब जिला प्रशासन की जांच पर निर्भर करेगा। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रमाणित होते हैं, तो यह केवल एक कर्मचारी की जवाबदेही का मामला नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता भी सामने आएगी।

यदि यह कवर स्टोरी प्रकाशित की जानी है, तो संबंधित पक्ष (आरोपित व्याख्याता या शिक्षा विभाग) का पक्ष भी शामिल करना पत्रकारिता और कानूनी दृष्टि से उचित रहेगा।

कलेक्टर ने की महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 9 जुलाई 2026/कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों, बच्चों की संख्या, जर्जर भवन, निर्माणाधीन भवन, पूर्ण भवन, टीकाकरण, पोषक आहार वितरण आदि का परियोजना और सेक्टर अधिकारियों से चर्चा कर समीक्षा किया। कलेक्टर ने कहा कि जर्जर भवनों में बच्चों को नहीं बैठाएं, वहाँ स्थित नवीन भवन या अतिरिक्त सरकारी भवन में बच्चों को बैठाएं। पालकों के साथ गृह भेंट और महिलाओं के साथ चौपाल कर बच्चों के देखरेख, सावधानी आदि के बारे में माताओं को सिखाएं। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे कुपोषित और मध्यम बच्चे हैं उन्हें एनआरसी केंद्र के माध्यम से सुपोषित करने के लिए पालक को प्रोत्साहित करने सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को निर्देशित करें ताकि कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं रहे। इसी प्रकार बच्चों को जन्मजात या अन्य गंभीर बीमारी ग्रस्त है तो उन्हें चिरायु टीम को जांच करने के लिए अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी देने के लिए निर्देशित करें। उन्होंने अधिकारियों और सुपरवाइजरों को महतारी वंदन योजना के नये पंजीयन नहीं हो रहा है इसकी जानकारी अपने क्षेत्र के महिलाओं को दें। कलेक्टर ने कहा कि गर्भवती और शिशुवती माता सहित 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण और घर पहुंच राशन शत प्रतिशत वितरित करें। उन्होंने आंगनबाड़ी समय पर खोलने, बच्चों की उपस्थिति के आधार पर भोजन, पोषक आहार तैयार करने और सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर को निर्देश दिए।

सारंगढ़ की फाइलों को मिली नई रफ्तार

6 अफसरों के कंधों पर बंटा जिले का प्रशासनिक बोझ, कलेक्टर ने जारी किया नया कार्य विभाजन

विशेष रिपोर्ट । सारंगढ़-बिलाईगढ़

सोमवार दोपहर कलेक्टर कार्यालय की दूसरी मंजिल पर असामान्य हलचल थी। फाइलें एक मेज से दूसरी मेज तक पहुंच रही थीं। कुछ ही देर बाद कलेक्टर के हस्ताक्षर के साथ जारी हुए ₹कार्य विभाजन आदेश₹ ने जिले के प्रशासनिक ढांचे की नई तस्वीर तय कर दी। अब किस अधिकारी के पास कौन-सी जिम्मेदारी होगी, किस टेबल पर कौन-सी फाइल पहुंचेगी और किस विभाग की जवाबदेही किसके कंधों पर होगी—इसकी स्पष्ट रूपरेखा सामने आ गई। 7 जुलाई 2026 को जारी यह आदेश केवल विभागों का बंटवारा नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और कार्यकुशलता को नई दिशा देने की पहल माना जा रहा है।

जिला पंचायत से विकास की कमान संभालेंगे इन्द्रजीत बर्मन

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) इन्द्रजीत बर्मन के जिम्मों में सबसे व्यापक दायरा शामिल किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के साथ-साथ शिक्षा, स्वच्छ भारत मिशन, कृषि, रेशम, पशुपालन और बहुचर्चित पीएम सूर्यघर योजना की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है। इसके अलावा सूचना का अधिकार (आरटीआई) की अपीलों का निस्तारण भी अब उनके अधिकार क्षेत्र में रहेगा। यानी गांवों के विकास से लेकर सरकारी योजनाओं की निगरानी तक कई अहम जिम्मेदारियां अब एक ही अधिकारी के पास केंद्रित होंगी।

सारंगढ़ की प्रशासनिक कमान उमेश कुमार साहू के हाथों में

डिप्टी कलेक्टर उमेश कुमार साहू को सारंगढ़ का नया अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) – एसडीएम नियुक्त किया गया है।

अब कानून-व्यवस्था, राजस्व प्रकरण, भू-अर्जन, बेदखली, अतिक्रमण, भूमि विवाद और

प्रशासनिक समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं के पास होगी। इसके साथ ही जिला सत्कार अधिकारी, जनगणना और निर्वाचन संबंधी कार्यों का दायित्व भी उन्हें सौंपा गया है।

न्यायिक मामलों की जिम्मेदारी ऋचा सिंह को

डिप्टी कलेक्टर ऋचा सिंह को न्यायालयीन एवं अर्द्धन्यायिक प्रकरणों का दायित्व सौंपा गया है। किराया नियंत्रण, नजूल भूमि विवाद, ई-कोर्ट से जुड़े प्रकरण, ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्र सहित कई संवेदनशील मामलों का निराकरण अब उनके अधिकार क्षेत्र में होगा। प्रशासनिक न्याय व्यवस्था को गति देने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

भूमि रिकॉर्ड से राहत कार्य तक, डॉ. वर्षा बंसल के जिम्मे बड़ा दायरा

डिप्टी कलेक्टर डॉ. वर्षा बंसल को भू-अभिलेख, राजस्व रिकॉर्ड, जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्रों से जुड़े मामलों, राहत एवं पुनर्वास कार्य, प्राकृतिक आपदा से जुड़े प्रकरण तथा जन सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा नगरीय प्रशासन, खाद्य एवं औषधि विभाग, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के समन्वय की जिम्मेदारी भी उनके पास रहेगी। प्रशासनिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त विभागों में से एक माना जाता है।

बिलाईगढ़ की कमान संभालेंगे प्रफुल्ल रजक

डिप्टी कलेक्टर प्रफुल्ल रजक को बिलाईगढ़ का एसडीएम बनाया गया है। बिलाईगढ़ अनुविभाग में राजस्व, भू-अर्जन, कानून-व्यवस्था, भाड़ा नियंत्रण तथा प्रशासनिक समन्वय से जुड़े सभी प्रमुख कार्य अब उनके नेतृत्व में संचालित होंगे।

जनता से सीधा संवाद करेंगी शिक्षा शर्मा

डिप्टी कलेक्टर शिक्षा शर्मा को आम नागरिकों से सीधे जुड़े सबसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकारी आवास आवंटन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, जनसमस्या निवारण शिविर, समय-सीमा (टीएल) प्रकरण, विभिन्न परीक्षाओं की नोडल अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग एवं जिला अस्पताल के समन्वय जैसे महत्वपूर्ण दायित्व अब उनके पास रहेंगे। यानी आम जनता की शिकायतों और समाधान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होगी।

काम न रुके, इसलिए बनी 'लिंक ऑफिसर' व्यवस्था

प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान न आए, इसके लिए आदेश में लिंक ऑफिसर व्यवस्था भी लागू की गई है।यदि कोई अधिकारी अवकाश पर रहता है या अनुपस्थित होता है, तो उसका कार्य निर्धारित दूसरे अधिकारी द्वारा संभाला जाएगा। इससे फाइलों के लंबित रहने की संभावना कम होगी और प्रशासनिक कामकाज में निरंतरता बनी रहेगी।

कलेक्टर ने दिया स्पष्ट संदेश

कार्य विभाजन आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। साथ ही जिन विभागों या विषयों का उल्लेख आदेश में नहीं किया गया है, वे सीधे कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे।

जनता के लिए क्या बदलेगा?

इस नए कार्य विभाजन का सबसे बड़ा प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ेगा। अब लोगों को यह स्पष्ट रहेगा कि किस प्रकार की समस्या या आवेदन लेकर किस अधिकारी के पास जाना है।

मानवता की मिसाल: 10 साल बाद मां को जीवित देख बिलख पड़ा पूरा परिवार, समाज सेवी सुरेश निर्मलकर बने सूत्रधार

बेमेतरा से बालोद पहुंचे बेटा-बेटी, मां को सही-सलामत पाकर आंखों से बहे खुशी के आंसू

न्यूज़ रुटीन @ बालोद:

जिनका कोई नहीं सहारा, उनका ईश्वर सहारा होता है।*₹ इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करते हुए बालोद के प्रबुद्ध समाजसेवी सुरेश निर्मलकर, एल्डरमैन श्रीमती हितेश्वरी कौशिक और शिव कृपा महिला मानस मंडली की मातृशक्तियों के अथक प्रयासों से एक ऐसा चमत्कार हुआ है, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं। 10 वर्षों से अपनी मां श्रीमति चंद्रप्रभा को मृत मान चुके बच्चों को न सिर्फ उनकी मां वापस मिली, बल्कि वर्षों बाद पूरा बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो गया।

अस्पताल में भर्ती होने से शुरू हुई खोज

मामला तब प्रकाश में आया जब लगभग 70 वर्षीय बुजुर्ग श्रीमति चन्द्रप्रभा माता जी का स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें जिला अस्पताल बालोद में भर्ती कराया गया था। वे दो दिन बेहोश रहीं और उन्हें ऑक्सीजन लगाया गया था। अस्पताल में एक सप्ताह के इलाज के बाद जब माता जी की सेहत में सुधार हुआ, तो उनके परिजनों की खोजबीन शुरू की गई। उनके पास कोई संपर्क नंबर भी नहीं था।

समाजसेवी सुरेश निर्मलकर की मेहनत लाई रंग

आश्चर्य की बात यह थी कि इन 10 वर्षों में माता जी ने कभी भी अपने परिवार का जिक्र नहीं किया और न ही कभी बताया कि उनका कोई अपना भी है। इसके बावजूद समाजसेवी सुरेश निर्मलकर ने तत्परता दिखाते हुए उनके परिवार का पता लगाना शुरू किया। कड़े प्रयासों और गहन खोजबीन के बाद आखिरकार उन्हें सफलता मिली। पता चला कि बुजुर्ग माता जी के बेटा लखन मानिकपुरी ग्राम जेवरा और बेटी सोनी मानिकपुरी (पति मनहरण) ग्राम खैरझिटी, जिला बेमेतरा में निवास करते हैं। सुरेश जी ने इधर-उधर कई तरह से संपर्क साधा और उनके परिवार को उनकी मां के स्वस्थ, जीवित और सकुशल होने की जानकारी दी।

दस साल बाद बालोद में हुआ भावुक महामिलन

माता जी के बेटा-बेटी का पिछले 10 सालों से उनसे कोई संपर्क नहीं था। वे यह आस पूरी तरह छोड़ चुके थे कि उनकी मां इस दुनिया में हैं; जैसे ही उन्हें मां के जीवित होने की सूचना मिली, वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। आज वह ऐतिहासिक क्षण आया जब बुजुर्ग माता जी से मिलने उनका पूरा परिवार एक साथ बालोद पहुंचा। 10 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जैसे ही बच्चों और परिवार के सदस्यों ने अपनी बुजुर्ग मां को जीवित सामने देखा, तो बरसों का दर्द आंसू बनकर बह निकला। परिवार के सभी सदस्य माता जी से लिपटकर फफक-फफक कर रो पड़े। वहां मौजूद हर शख्स की आंखें इस दृश्य को देखकर नम हो गईं। पूरा परिवार अपनी मां को दोबारा पाकर भाव-विभोर हो गया और आदर पूर्वक उन्हें अपने साथ घर ले गया।

एल्डरमैन हितेश्वरी कौशिक और मानस मंडली का सराहनीय योगदान

इस पूरे सफर में एल्डरमैन श्रीमती हितेश्वरी कौशिक का मार्गदर्शन और योगदान अत्यंत सराहनीय वंदनीय रहा। उनके साथ ही शिव कृपा महिला मानस मंडली की अध्यक्ष कल्याणी कौशिक, श्रीमती अनीता देशमुख, रेखा यादव, गुनीता साहू, सुशीला यादव, निर्मला यादव, यशोदा यादव, गंगा शर्मा सहित मंडली के सभी सदस्यों ने पिछले 10 वर्षों से इस बुजुर्ग माता जी को अपने स्वयं के परिवार के सदस्य की भांति रखा। उनकी हर छोटी-बड़ी जरूरत का ध्यान रखना, बीमारी में निस्वार्थ सेवा करना और उन्हें कभी अकेलेपन का अहसास न होने देना, उनकी उच्च सोच और सेवा भाव को दर्शाता है।

समाज में सराहना: एक अनुकरणीय मिसाल

आज के दौर में जहां लोग अपनों को भूल जाते हैं, वहीं समाज सेवी सुरेश निर्मलकर, एल्डरमैन हितेश्वरी कौशिक और शिव कृपा महिला मानस मंडली का यह सेवा भाव और समर्पण समाज के लिए एक महान प्रेरणा है। बिछड़े हुए पूरे परिवार को दोबारा मिलाने में जो अहम भूमिका निभाई है, उसकी पूरे नगर और क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है।

न्यूज़ रूटीन @ बालोद।

गुरूर विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बड़भूम परिसर में बिना अनुमति 29 हरे-भरे पेड़ों की कटाई के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रधान पाठक डोमार सिंह निषाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई दुर्ग शिक्षा संभाग के संयुक्त संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर की है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय डौंडीलोहारा से संबद्ध किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि विद्यालय परिसर में पेड़ों की कटाई बिना सक्षम अनुमति कराई गई तथा इसकी सूचना उच्च कार्यालय को भी नहीं दी गई। विभाग ने इसे शासकीय दायित्वों की अवहेलना, गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई की है। आदेश की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, संभागायुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, जिला शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।

समिति के प्रस्ताव पर हुई थी कटाई

शिक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट के अनुसार 23 अप्रैल को शाला विकास समिति की बैठक आयोजित कर पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव पारित किया गया था। हालांकि प्रस्ताव केवल पेड़ों की डालियां छंटाई से संबंधित बताया गया, लेकिन इसके बाद परिसर के लगभग 29 हरे-भरे पेड़ काट दिए गए। जांच में सामने आया कि पूरी प्रक्रिया प्रधान पाठक एवं शाला विकास समिति के सचिव डोमार सिंह निषाद की निगरानी में हुई और किसी सक्षम विभाग से अनुमति नहीं ली गई।

पांच दिन बाद भी दर्ज नहीं हुई एफआईआर

पेड़ों की अवैध कटाई की पुष्टि होने के बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी गुरूर ने 3 जुलाई को थाना गुरूर में दोषियों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। इसके बावजूद पांच दिन बाद भी मामला दर्ज नहीं किया गया। जानकारी के अनुसार जिस भूमि पर पेड़ों की कटाई हुई है, वह वन विभाग की नहीं बल्कि राजस्व विभाग की भूमि है। इसी कारण पुलिस ने पहले भूमि की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। वन विभाग अपनी जांच रिपोर्ट राजस्व विभाग को सौंप चुका है, जबकि अब एसडीएम स्तर पर मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी ।

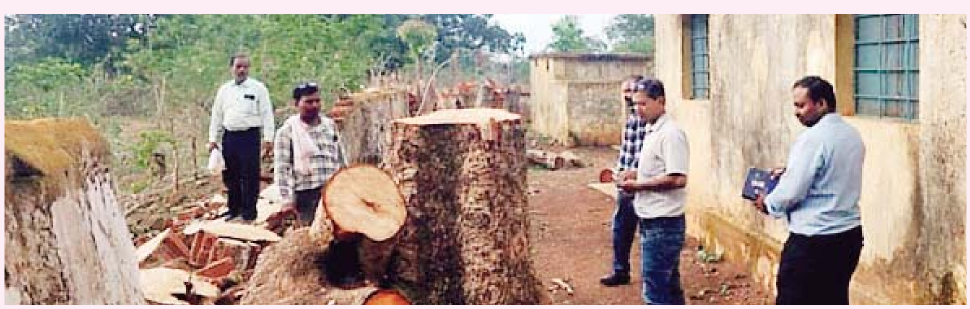

न्यूज रुटीन @ बिलासपुर।

बिलासपुर जिले के तखतपुर क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत से निर्माणाधीन एनएच-130ए सड़क परियोजना अब गंभीर सवालों के घेरे में है। सड़क पूरी होने से पहले ही कई स्थानों पर बने निर्माण को तोड़ा जा रहा है। ठेकेदार द्वारा स्वयं ही तैयार किए गए हिस्सों को ध्वस्त किए जाने से निर्माण की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप किया गया था, तो उसे दोबारा तोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

तखतपुर के मोढ़े मार्ग से मनियारी पुल तक सड़क चौड़ीकरण एवं नाली निर्माण का कार्य जारी है। हैरानी की बात यह है कि निर्माण स्थल पर न तो परियोजना से संबंधित कोई सूचना पटल लगाया गया है और न ही निर्माण एजेंसी का स्थानीय कार्यालय दिखाई देता है। ऐसे में लोगों को यह तक जानकारी नहीं है कि परियोजना की कुल लागत कितनी है, निर्माण कार्य किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है और इसे कब तक पूरा किया जाएगा।

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी मौके पर निरीक्षण करने के बजाय केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित हैं। इसी का लाभ उठाकर ठेकेदार मनमाने ढंग से कार्य कर रहा है। कई स्थानों पर पहले से बने हिस्सों को तोड़ने की स्थिति ने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और कार्य की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।

नियमों के अनुसार किसी भी सरकारी निर्माण स्थल पर परियोजना की लागत, कार्यदायी संस्था, निर्माण अवधि और संबंधित अधिकारियों की जानकारी प्रदर्शित करने वाला सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होता है। लेकिन इस परियोजना में यह व्यवस्था भी नजर नहीं आ रही है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब निर्माण कार्य शुरुआती चरण में ही टूटने लगे, तो ऐसी सड़क भविष्य में वर्षों तक भारी यातायात का भार कैसे सहन करेगी? क्षेत्रवासियों ने पूरे निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जांच कराने, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच कराने तथा लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में घटिया निर्माण, नियमों की अनदेखी या वित्तीय अनियमितता सामने आती है, तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर जनता के पैसों की बर्बादी रोकनी चाहिए। क्षेत्रवासियों का कहना है, जब करोड़ों रुपये की सड़क निर्माणाधीन अवस्था में ही टूटने लगे, तो यह गुणवत्ता और जवाबदेही दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जनता बेहतर सड़क चाहती है, लेकिन उसे गुणवत्ता के बजाय लापरवाही और बहानों का सामना करना पड़ रहा है।

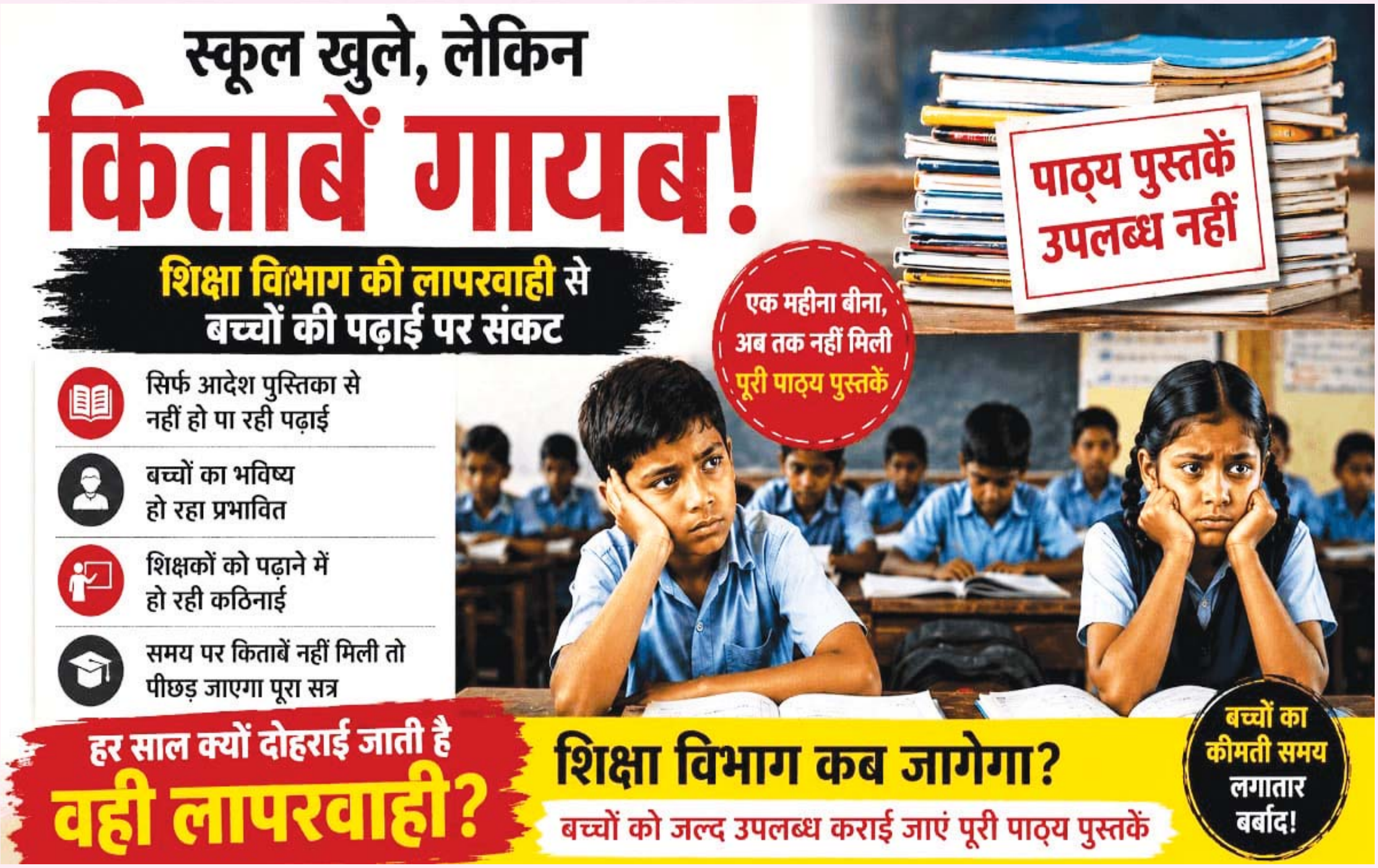

न्यूज रुटीन @ सरसींवा (सारंगढ़-बिलाईगढ़)

नया शिक्षा सत्र शुरू हुए लगभग एक माह होने वाला है, लेकिन क्षेत्र के कई शासकीय स्कूलों में आज भी बच्चों को पूरी पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं। स्कूलों में पढ़ाई तो शुरू हो गई है, लेकिन किताबों के बिना बच्चे सिर्फ शिक्षक की बात सुनने तक सीमित हैं। घर जाकर पढ़ाई करने और अभ्यास करने का कोई साधन नहीं होने से उनकी पढ़ाई लगातार पिछड़ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी उन गरीब परिवारों के बच्चों को हो रही है, जो बाजार से किताबें खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। बिना किताबों के वे न तो पाठ समझ पा रहे हैं और न ही परीक्षा की तैयारी कर पा रहे हैं। नई कक्षा का पहला महीना लगभग खत्म होने को है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाया है। इसका असर सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, बल्कि शिक्षकों पर भी पड़ रहा है। किताबें नहीं होने से शिक्षक पूरे पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं। कई जगह उन्हें अलग-अलग नोट्स बनवाकर या बोर्ड पर लिखकर पढ़ाना पड़ रहा है, जिससे समय भी बर्बाद हो रहा है और पढ़ाई की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में समय पर सिलेबस पूरा करना भी बड़ी चुनौती बन गया है।

हैरानी की बात यह है कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। पिछले शैक्षणिक सत्र में भी कई विद्यार्थियों को समय पर किताबें नहीं मिल सकी थीं। हर साल वही लापरवाही, वही बहाने और नुकसान सिर्फ बच्चों का। सवाल यह है कि जब स्कूल खुलने की तारीख पहले से तय रहती है, तब किताबों की छपाई और वितरण की तैयारी समय रहते क्यों नहीं की जाती? आखिर हर साल बच्चों के भविष्य के साथ यही लापरवाही क्यों दोहराई जाती है?

शिक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। करोड़ों रुपये खर्च होने के दावे किए जाते हैं, फिर भी बच्चों के हाथों तक समय पर किताबें नहीं पहुंच पा रही हैं। विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली का खामियाजा मासूम विद्यार्थी भुगत रहे हैं।

अब अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मांग की है कि सभी स्कूलों में तत्काल पूरी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं, ताकि बच्चों की पढ़ाई पटरी पर लौट सके। यदि जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी, तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों के परिणाम, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और उनके भविष्य पर पड़ेगा।

न्यूज़ रूटीन @ धमतरी

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के मगरलोड जनपद क्षेत्र में वर्ष 2007 की शिक्षाकर्मी भर्ती प्रक्रिया में हुए कथित फर्जीवाड़े पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आठ कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। विभागीय जांच में इन कर्मचारियों की नियुक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर होना प्रमाणित होने के बाद यह सख्त फैसला लिया गया। इस कार्रवाई से जिले के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अन्य मामलों की भी जांच तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

आरटीआई से खुला फर्जीवाड़े का मामला

जानकारी के अनुसार वर्ष 2007 में शिक्षाकर्मी भर्ती के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी। लंबे समय तक यह मामला सामने नहीं आया, लेकिन बाद में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत भर्ती से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई। जांच में दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताओं और फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने विभागीय जांच शुरू की।

विभागीय जांच में हुई पुष्टि

करीब कई वर्षों तक चली जांच के दौरान संबंधित अभिलेखों, प्रमाण पत्रों और भर्ती प्रक्रिया का परीक्षण किया गया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आठ कर्मचारियों की नियुक्ति नियमों के विपरीत और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग ने सभी कर्मचारियों को सेवा से पृथक करने का आदेश जारी कर दिया।

18 वर्षों तक करते रहे नौकरी बने प्रधानपाठक

बताया जा रहा है कि जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, वे पिछले लगभग 18 वर्षों से शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। इस दौरान उन्हें पदोन्नति भी मिली और वे प्रधानपाठक (हेड मास्टर) के पद तक पहुंच गए थे। हालांकि जांच पूरी होने के बाद विभाग ने उनकी नियुक्ति को अवैध मानते हुए सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया।

अन्य मामलों की भी हो सकती है जांच

इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार शिक्षाकर्मी भर्ती से जुड़े अन्य मामलों और दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। यदि अन्य मामलों में भी अनियमितताएं सामने आती हैं तो आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाई होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

पारदर्शिता और जवाबदेही का संदेश

शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई को सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विभाग का मानना है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी सेवा प्राप्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर रोक लगाने में प्रभावी साबित होगी। साथ ही यह संदेश भी जाएगा कि किसी भी स्तर पर फर्जीवाड़ा करने वालों को कानून और विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

न्यूज रूटीन @ सारंगढ़-बिलाईगढ़

यदि कोई जागरूक नागरिक ठान ले तो व्यवस्था को जवाब देना ही पड़ता है। ग्राम पंचायत पिरदा में मनरेगा के तहत कराए गए आरसीसी नाली निर्माण कार्य इसका ताजा उदाहरण बनकर सामने आया है। ग्राम भिनोदा निवासी गोपी अजय द्वारा CPGRAMS पोर्टल पर दर्ज एक शिकायत ने उन निर्माण कार्यों को जांच के दायरे में ला दिया, जिन पर सरकारी धन खर्च हो चुका था। जांच पूरी होने के बाद जो तथ्य सामने आए, उन्होंने पंचायत स्तर पर कराए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनपद पंचायत बिलाईगढ़ द्वारा कराए गए तकनीकी मूल्यांकन में तीन अलग-अलग नाली निर्माण कार्यों का पुनर्मूल्यांकन किया गया। जांच में स्वीकृत कार्य और स्थल पर उपलब्ध कार्य में अंतर पाए जाने के बाद लोहरिनडीपा तालाब से भोरकाडीपा की ओर बने नाली निर्माण कार्य में 4.06 लाख रुपये, भोरकाडीपा से नाला तक बने नाली निर्माण कार्य में 2.68 लाख रुपये तथा डीपापारा से सामुदायिक भवन की ओर बने नाली निर्माण कार्य में 2.87 लाख रुपये की कटौती प्रस्तावित की गई। यानी केवल तीन कार्यों में ही कुल 9.61 लाख रुपये की कटौती की अनुशंसा करनी पड़ी।

इसके बाद जिला पंचायत सारंगढ़-बिलाई-गढ़ ने भी आधिकारिक पत्र जारी कर उक्त कटौती को विलोपन की कार्रवाई के लिए कलेक्टर को भेज दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि शिकायत नहीं होती तो क्या इन निर्माण कार्यों का दोबारा तकनीकी परीक्षण होता? क्या लाखों रुपये की यह कटौती कभी सामने आती? सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि शिकायत के बाद ही जांच हुई, पुनर्मूल्यांकन हुआ और फिर कटौती की अनुशंसा की गई। यह घटनाक्रम बताता है कि विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जनभागी-दारी और शिकायत तंत्र कितने महत्वपूर्ण हैं। यह मामला केवल एक पंचायत तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि यह उन तमाम विकास कार्यों की निगरानी व्यवस्था पर भी प्रश्न खड़ा करता है, जिनका भुगतान सरकारी राशि से किया जाता है। जब कार्यों का तकनीकी परीक्षण और माप पुस्तिका के आधार पर भुगतान किया जाता है, तब ऐसी स्थिति कैसे बनी कि बाद में पुनर्मूल्यांकन कर लाखों रुपये की कटौती प्रस्तावित करनी पड़ी? यह सवाल अब प्रशासनिक व्यवस्था के सामने खड़ा है। फिलहाल ग्रामीणों की नजर अब आगे की कार्रवाई पर है। क्या प्रस्तावित कटौती के बाद जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी, शासकीय राशि की वसूली होगी और दोष पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी, या मामला केवल पत्राचार और फाइलों तक सीमित रह जाएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में प्रशासनिक कार्रवाई से ही मिलेगा। हालांकि इतना तय है कि एक शिकायत ने न केवल लाखों रुपये के सरकारी कार्यों की जांच कराई, बल्कि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी नई बहस छेड़ दी है।

लोककला की अमर स्वर-सरिता को राजकीय सम्मान पद्म विभूषण तीजन बाई को अश्रुपूरित विदाई

न्यूज़ रुटीन @ रायपुर

छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्वविख्यात पंडवानी गायिका एवं पद्म विभूषण से सम्मानित डॉ. तीजन बाई को रविवार को उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। राज्य शासन के निर्णय के अनुरूप पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कलाकारों, साहित्यकारों तथा हजारों श्रद्धालुओं ने नम आंखों से लोककला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया।डॉ. तीजन बाई के निधन से न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश के कला एवं सांस्कृतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने अद्वितीय गायन, प्रभावशाली अभिनय और ओजपूर्ण प्रस्तुति के माध्यम से पंडवानी जैसी लोककला को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। महाभारत की कथाओं को जीवंत शैली में प्रस्तुत करने की उनकी विलक्षण कला ने देश-विदेश के असंख्य दर्शकों को भारतीय लोकसंस्कृति से जोड़ने का कार्य किया। ग्रामीण परिवेश से निकलकर विश्व मंच तक पहुंचने का उनका सफर संघर्ष, साधना और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। अनेक सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर ऐसी पहचान बनाई, जिसने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बनी रहेंगी। भारतीय लोककला में उनके अप्रतिम योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण सहित अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया गया। वे भारतीय लोक परंपरा की ऐसी प्रतिनिधि थीं, जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से देश की सांस्कृतिक अस्मिता को विश्वभर में गौरवान्वित किया।

राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप उनके अंतिम संस्कार के अवसर पर राजकीय सम्मान की सभी औपचारिकताएं पूर्ण की गईं। गनियारी गांव में आयोजित अंतिम संस्कार में उपस्थित जनसमूह ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को सदैव जीवित रखने का संकल्प व्यक्त किया। डॉ. तीजन बाई का निधन भारतीय लोककला के एक स्वर्णिम युग का अवसान है, किंतु उनकी स्वर-साधना, पंडवानी की समृद्ध परंपरा और लोकसंस्कृति के संरक्षण के लिए उनका आजीवन समर्पण सदैव अमर रहेगा। उनकी अनुपम कला, ओजस्वी व्यक्तित्व और सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करती रहेगी।

पंडवानी की अमर स्वर-गाथा: तीजन बाई को सांगीतिक श्रद्धांजलि

पद्मविभूषण डॉ. तीजन बाई के नाम पर पंडवानी कला के क्षेत्र में प्रतिवर्ष राज्य सम्मान की घोषणा

न्यूज़ रुटीन @रायपुर

छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने वाली पंडवानी की महान साधिका पद्म विभूषण डॉ. तीजन बाई को रायपुर में आयोजित एक भव्य सांगीतिक श्रद्धांजलि समारोह में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस आयोजन में न केवल उनकी कला साधना को याद किया गया, बल्कि उनकी विरासत को संरक्षित और आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गईं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी।

भावनाओं से भरा श्रद्धांजलि समारोह

महंत घासीदास संग्रहालय परिसर के मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित इस कार्यक्रम में लोककला, साहित्य और संस्कृति जगत की प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लेकर डॉ. तीजन बाई के अद्वितीय योगदान को स्मरण किया। कार्यक्रम में उनकी जीवन यात्रा, साधना और सांस्कृतिक प्रभाव को विभिन्न माध्यमों से प्रस्तुत किया गया।

तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने डॉ. तीजन बाई की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए तीन प्रमुख घोषणाएं कीं.

- **उनके नाम पर पंडवानी कला के क्षेत्र में प्रतिवर्ष राज्य सम्मान**
- **उनके जन्मस्थान गनियारी को "कलाग्राम" के रूप में विकसित करना**
- **उनके प्रिय तंबूरे को संग्रहालय में संरक्षित और प्रदर्शित करना**
- **इन घोषणाओं को लोककला संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।**

परिवार का सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव

कार्यक्रम में तीजन बाई की पुत्रवधु वेणु

देशमुख को एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। उन्होंने इस सम्मान को संपूर्ण लोककला परंपरा का सम्मान बताते हुए आभार व्यक्त किया।

'स्वर कभी मौन नहीं होते'

संस्कृति मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि तीजन बाई का स्वर छत्तीसगढ़ की लोकआत्मा का अमर नाद है।

उन्होंने कहा कि वे केवल एक लोकगायिका नहीं, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक अस्मिता की सजीव पहचान थीं। उनकी लोकधुनें आने वाली पीढ़ियों को संस्कृति और परंपरा से जोड़ती रहेंगी।

संगीत और स्मृतियों का संगम

कार्यक्रम की शुरुआत पंडवानी गायन से हुई, जिसके बाद उनके शिष्यों ने कापालिक और वेदमती शैली में प्रभावशाली प्रस्तुतियां दीं। इन प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। साथ ही, उनके जीवन पर आधारित वृत्तचित्र और विशेष ब्रोशर का विमोचन भी किया गया।

तीजन बाई – लोकसंस्कृति की वैश्विक पहचान

डॉ. तीजन बाई ने पंडवानी जैसी पारंपरिक लोककला को न केवल जीवित रखा, बल्कि उसे अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। उनकी प्रस्तुति शैली, स्वर की गूंज और कथन की जीवंतता ने उन्हें विशिष्ट पहचान दिलाई। उन्होंने महाभारत की कथाओं को लोकभाषा में इस तरह प्रस्तुत किया कि वह जन-जन तक सहज रूप से पहुंच सकीं। उनकी कला में लोकजीवन की सरलता और गहराई दोनों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनकी इस विरासत को संरक्षित करते हुए नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, ताकि लोककला की यह धारा निरंतर प्रवाहित होती रहे।

संस्कृति संरक्षण का संकल्प

कार्यक्रम में वक्ताओं ने तीजन बाई को भारत रत्न देने और उनके नाम पर सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग भी रखी। यह उनकी महानता और प्रभाव का प्रमाण है। यह श्रद्धांजलि समारोह केवल एक स्मरण नहीं,

बल्कि सांस्कृतिक संकल्प का प्रतीक बना। डॉ. तीजन बाई का स्वर भले ही अब प्रत्यक्ष रूप से न सुनाई दे, लेकिन उनकी कला, उनकी साधना और उनकी सांस्कृतिक विरासत सदैव जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास को मिल रही अभूतपूर्व गति

छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विविध परंपराओं से है। बीते समय में जिन क्षेत्रों तक विकास की रोशनी पूरी तरह नहीं पहुंच पाई थी, वहां अब नई ऊर्जा और योजनाओं के माध्यम से बदलाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों ने एक नई गति प्राप्त की है, जिसका असर शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं में साफ तौर पर नजर आ रहा है।

न्यूज रुटीन @ रायपुर

राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास के जनदर्शन हॉल में आयोजित भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के छत्तीसगढ़ राज्य बोर्ड के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनजातीय विकास को लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि यह बोर्ड आदिवासी समाज के उत्थान और अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ जनजातीय बहुल राज्य है, जहां विशेष पिछड़ी जनजातियों सहित अनेक समुदाय अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ निवास करते हैं। ऐसे में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के राज्य बोर्ड का गठन एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समाज को संगठित करने और विकास की दिशा में नई ऊर्जा प्रदान करेगा। संघ का गौरवपूर्ण इतिहास और उसकी राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका इस दिशा में प्रेरणादायी रही है। उन्होंने यह भी बताया कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष रहे, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भी इसका नेतृत्व किया। यह तथ्य संस्था की ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाता है।

राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बस्तर अंचल में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में भी बस्तर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और परंपराएं पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

बीते दशकों में विकास से वंचित रहे कई गांवों तक अब योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की गई है। लगभग 400 गांवों का सर्वेक्षण कर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ा गया है। नियद नेल्लानार योजना के तहत 500 से अधिक गांवों में सड़क, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। साथ ही राशन कार्ड, उचित मूल्य दुकानों और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी तेजी से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 'मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर योजना' के अंतर्गत घर-घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय पर उपचार मिल सके। वहीं 'बस्तर मुन्ने' पहल के माध्यम से सुदूर वनांचलों तक शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।

जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए उन्हें शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसरों से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। यह संतुलन ही विकास को स्थायी और समावेशी बनाता है।

जनजातीय क्षेत्रों में विकास की नई धारा

राज्य में लंबे समय से उपेक्षित रहे दूरस्थ गांवों को अब योजनाओं के माध्यम से मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। सड़क, बिजली, पानी और राशन जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता ने इन क्षेत्रों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया है। नियद नेल्लानार योजना के जरिए सैकड़ों गांवों तक पहुंच बनाकर विकास को जमीनी स्तर तक उतारा गया है।

स्वास्थ्य और आजीविका में बढ़ता विश्वास

'स्वस्थ बस्तर योजना' और 'बस्तर मुन्ने' जैसे प्रयासों ने जनजातीय क्षेत्रों में भरोसे को मजबूत किया है। घर-घर स्वास्थ्य जांच और योजनाओं की सीधी पहुंच से लोगों को न केवल बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी विकसित हो रहे हैं। इससे आत्मनिर्भरता की दिशा में जनजातीय समाज तेजी से आगे बढ़ रहा है।

बदली बिलाईगढ़ के तिहारूराम की तकदीर

न्यूज रुटीन @ बिलाईगढ़

आधुनिक दौर में खेती-किसानी को उन्नत और मुनाफे का सौदा बनाने में कृषि यंत्रों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो चुकी है। राज्य शासन की कृषि यंत्रीकरण योजना आज छोटे और मझोले किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसका एक जीवंत उदाहरण विकासखण्ड बिलाईगढ़ के ग्राम गधाभाटा में देखने को मिला है, जहाँ के प्रगतिशील कृषक तिहारूराम चंद्रा पिता जगनथिया का खुद का ट्रैक्टर खरीदने का सपना साकार हुआ है। ग्राम झुमका में आयोजित भव्य सुशासन शिविर में प्रभारी मंत्री श्री टंकराम वर्मा के करकमलों से तिहारूराम को उनके नए ट्रैक्टर की चाबी सौंपी गई। ट्रैक्टर का 9.40 लाख रूपए की कुल लागत पर तिहारूराम को राज्य शासन की ओर से 4 लाख रूपए का भारी शासकीय अनुदान प्राप्त हुआ है। इस पर तिहारूराम ने कहा कि कम जमीन और सीमित साधनों के कारण पहले समय पर खेती का काम पूरा करना एक बड़ी चुनौती थी। भारी-भरकम किराए पर ट्रैक्टर लेना पड़ता था। लेकिन सरकार की इस योजना और 4 लाख रुपए की बड़ी छूट ने मेरी राह आसान कर दी। अब मैं न सिर्फ समय पर अपनी खेती कर सकूंगा, बल्कि खेती को अधिक आधुनिक और लाभकारी भी बना पाऊंगा।

वन स्टॉप सेंटर' से मिला किसानों को तत्काल लाभ

सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित इन शिविरों में कृषि विभाग द्वारा श्वन स्टॉप सेंटरश् के रूप में स्टाल लगाए गए थे। यहाँ आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के साथ-साथ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुँचाया गया। शिविर के दौरान विभाग को कुल 575 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें 545 मांग संबंधी और 30 शिकायत संबंधी मामले थे। विभाग ने संवेदनशीलता और मुस्तैदी दिखाते हुए रिकॉर्ड समय में 572 आवेदनों (544 मांग व 28 शिकायत) का सफलतापूर्वक निराकरण कर सुशासन की मिसाल पेश की।

उन्नत कृषि और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा

ट्रैक्टर वितरण के साथ ही विभाग द्वारा शिविर में उपस्थित किसानों को उन्नत एवं वैज्ञानिक खेती से जोड़ने के लिए नीम आधारित कीटनाशक, हरित खाद, प्रमाणित बीज और विभिन्न लघु कृषि यंत्रों का वितरण भी किया गया। उप संचालक कृषि, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों और ग्रामीण कृषि विकास अधिकारियों की टीम ने किसानों को चौपाल लगाकर केंद्र व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इनमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,सॉइल हेल्थ कार्ड योजना और एग्री स्टैक पंजीयन,प्राकृतिक व जैविक खेती मिशन तथा परंपरागत कृषि विकास योजना,दलहन-तिलहन प्रोत्साहन कार्यक्रम और हरित खाद का उपयोग शामिल है। जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में कृषि विभाग का यह महाअभियान न केवल किसानों की समस्याओं के प्रभावी समाधान का जरिया बना, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीकों से जोड़कर आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। यह पूरी मुहिम सुशासन, जनभागीदारी और किसान कल्याण का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरी है।

विकसित भारत का सपना, डिजीटल इंडिया की सोच लेकिन आज भी नहीं बदले गांव के हालात

न्यूज रुटीन @ बीजापुर

भोपालपटनम ब्लॉक मुख्यालय से महज 3 किमी दूर बसे ग्राम पंचायत रूद्रारम के आश्रित गांव बोरगुड़ा और भीमारमपारा जाने वाली मार्ग की बदहाली विकास के सारे दावों की पोल खोल रही है। लेकिन आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं। ताजा तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश शुरू होते ही पूरी सड़क कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो गई है। जगह-जगह

पानी भर जाने से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सड़क नहीं बनाये जाने से ग्रामीणों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है। छात्र-छात्राएं रोजाना कीचड़ से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। कई जगह सड़क इतनी खराब है कि बच्चों को गड्ढों और पानी से बचते हुए घंटों पैदल चलना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में आवाजाही का एकमात्र सड़क गड्ढों और कीचड़ में तब्दील हुआ है, जिससे रोजाना कई बाइक चालक फिसलन से गिर जाते हैं। रास्ता कीचड़नुमा होने के कारण एम्बुलेंस का निकलना भी जोखिम भरा हो जाता है।

वर्षों से पक्की सड़क मांग अधूरी

ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क की मांग वर्षों से की जा रही है। कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को आवेदन देने के बावजूद अब तक पक्की सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। चुनाव के दौरान कई जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया था लेकिन ढ़ाई वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक समाधान नहीं मिला है।

शासन प्रशासन से किया तत्काल राहत की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग किया है कि बरसात के दौरान होने वाली परेशानी को देखते हुए तत्काल सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया जाए, ताकि स्कूली बच्चों, किसानों और ग्रामीणों को राहत मिल सके।

पक्की सड़क के इंतजार में राह देखते ग्रामवासी

२वर्षों से पक्की सड़क निर्माण के लिए राह देखते ग्रामवासियो ने कहा कि अब और देरी नहीं होनी चाहिए। हर बारिश में यही परेशानी झेलनी पड़ती है। बच्चों की पढ़ाई और गांव की आवाजाही दोनों प्रभावित हो रही हैं। प्रशासन जल्द समाधान करे।

3 बार सर्वे लेकिन स्वीकृति नहीं

सरपंच चंदा दुर्गम ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य के लिए PMGSY फेस 4 के तहत स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में तीन बार सर्वे कार्य कराया गया लेकिन अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं हुई।

सीसी सड़क स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा पत्र

इस संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा ने बताया कि कच्ची मार्ग की खराबी को देखते हुए सीसी सड़क निर्माण कार्य स्वीकृति हेतु ग्राम गौरव पथ योजना से मुख्य अभियंता को पत्र प्रेषित किया जाएगा। स्वीकृति उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस संबंध में सीईओ जनपद पंचायत भोपालपटनम आदित्य कुंजाम ने बताया कि वर्तमान में PMGSY 4 में छूटे सड़कों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2.0 के प्रावधानों में लिया जा रहा है। स्थल निरीक्षण कर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा जाएगा।

उद्योगों के साथ पर्यावरण संरक्षण की नई साझेदारी

औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को अक्सर एक-दूसरे के विरोधी रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन बदलते समय में यह धारणा तेजी से बदल रही है। अब विकास का अर्थ केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ना है। छत्तीसगढ़ में इसी सोच के साथ उद्योगों और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक नई साझेदारी विकसित होती दिखाई दे रही है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य की दिशा तय कर रही है।

न्यूज रुटीन @ रायपुर

राजधानी रायपुर में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने मानसून-2026 के दौरान औद्योगिक इकाइयों द्वारा संचालित वृक्षारोपण कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य में औद्योगिक विकास और पर्यावरणीय संतुलन को साथ लेकर आगे बढ़ने की नीति अपनाई जा रही है। बैठक में प्रमुख औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ विभागीय अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी रही। मंत्री ने कहा कि विकसित भारत-2047 के विजन के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन यह विकास पर्यावरणीय मानकों के साथ ही संभव है। उन्होंने दो टूक कहा कि निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा, परंतु पर्यावरणीय नियमों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। वृक्षारोपण के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि केवल पौधे लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका संरक्षण और जीवित रखना ही वास्तविक जिम्मेदारी है। सही समय पर उपयुक्त प्रजातियों का चयन, नियमित सिंचाई और देखभाल के माध्यम से ही हरित आवरण को स्थायी बनाया जा सकता है। पीपल, नीम, शिरीष, आम और कटहल जैसे देशी एवं दीर्घायु वृक्षों को प्राथमिकता देने की बात कही गई, साथ ही मियावाकी जैसी आधुनिक पद्धतियों को अपनाने पर भी बल दिया गया।

बैठक में उद्योगों को निर्देशित किया गया कि वे अपने परिसरों और आसपास हरित वातावरण विकसित करें। 31 जुलाई तक वृक्षारोपण लक्ष्य पूर्ण करने और 15 अगस्त तक गुणवत्तापूर्ण पौधरोपण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली को अनिवार्य बनाया गया है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। पर्यावरण संरक्षण को नैतिक जिम्मेदारी बताते हुए यह स्पष्ट किया गया कि स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल और सुरक्षित पर्यावरण केवल वर्तमान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उद्योगों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के माध्यम से भी व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने और जनसहभागिता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। नवा रायपुर को पीपल सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। पूर्व में लगाए गए हजारों पौधों के अतिरिक्त आगामी वर्षों में एक लाख से अधिक पीपल के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सेंध लेक के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण के कार्यों के साथ जल संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। झील के मध्य विकसित किए जा रहे ₹बर्ड आइलैंड₹ के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को एक साथ बढ़ावा मिलने की संभावना है।राज्य में पर्यावरणीय निगरानी प्रणाली को भी सुदृढ़ किया गया है। सैकड़ों औद्योगिक इकाइयों में ऑनलाइन उत्सर्जन निगरानी प्रणाली लागू कर प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित किया जा रहा है।

हरित विकास की ओर बढ़ते कदम

औद्योगिक इकाइयों को अपने परिसर के कम से कम 33 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रति हेक्टेयर 2,500 पौधों का रोपण और त्रि-स्तरीय पौधरोपण की व्यवस्था से हरित आवरण को सघन और प्रभावी बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। यह पहल उद्योगों को पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील बना रही है।

तकनीक से पारदर्शिता और संरक्षण

ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से वृक्षारोपण और उत्सर्जन दोनों की निगरानी की जा रही है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि पर्यावरणीय नियमों के पालन को भी मजबूती मिली है। पुनर्चक्रित जल का उपयोग, देशी प्रजातियों का रोपण और मियावाकी जैसी तकनीकों का प्रयोग पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा दे रहा है।

राजनांदगांव में विकास को नई गति, ग्रामीण अधोसंरचना और कृषि सुधार पर जोर

ग्रामीण विकास और कृषि सशक्तिकरण किसी भी प्रदेश की प्रगति की मजबूत आधारशिला होते हैं। जब अधोसंरचना, कृषि नवाचार और जनसहभागिता एक साथ आगे बढ़ते हैं, तब विकास का दायरा व्यापक और स्थायी बनता है। राजनांदगांव में हुए विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम ने इसी समन्वित सोच को नई दिशा दी है, जहां गांवों के बुनियादी ढांचे के साथ किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष फोकस दिखाई दिया।

न्यूज रुटीन @ राजनांदगांव

राजनांदगांव स्थित आदर्श कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने लगभग 20 करोड़ 1 लाख 67 हजार रूपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम तथा सांसद संतोष पाण्डेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंतर्गत मंडी निधि से 2 करोड़ 39 लाख 17 हजार रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही विकासखंड की ग्राम पंचायतों में 16 करोड़ 32 लाख 98 हजार रूपए की लागत से 181 विकास कार्यों का भूमिपूजन तथा 9 ग्राम पंचायतों में 1 करोड़ 29 लाख 52 हजार रूपए की लागत से निर्मित 18 कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस दौरान 13 क्लस्टर की 51 ग्राम पंचायतों के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। कार्यक्रम में किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करते हुए अरहर और सोयाबीन के बीज वितरित किए गए। वहीं अंत्योदय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मिनीमाता महिला स्वसहायता समूह को व्यवसाय संचालन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिससे ग्रामीण महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा को बल मिला।

ग्रामीण अधोसंरचना और गुणवत्ता पर जोर

मंडी निधि का उपयोग ग्रामीण अधोसंरचना के विकास में अधिकाधिक किए जाने पर जोर दिया गया, ताकि गांवों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो सके। आदर्श कृषि उपज मंडी को प्रदेश की प्रमुख मंडियों में शामिल बताते हुए यहां उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं—मॉल, सिनेमा, विश्राम गृह, बैंक, पोस्ट ऑफिस, धर्मकांटा और विभिन्न मंडियों—का उल्लेख किया गया।फसल विविधीकरण को समय की आवश्यकता बताते हुए धान के साथ-साथ मक्का और सोयाबीन जैसी कम पानी वाली फसलों को अपनाने पर बल दिया गया, जिससे किसानों की आय में वृद्धि और जल संरक्षण दोनों संभव हो सके। साथ ही पंचायत भवन, सीसी रोड, खेल मैदान और अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

प्रदेश में कृषि को टिकाऊ और लाभकारी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। धान के स्थान पर अन्य फसलें लेने वाले किसानों को 15 हजार रूपए प्रति एकड़ की सहायता प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। अत्यधिक धान उत्पादन से भू-जल स्तर में गिरावट और भूमि की उर्वरता पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कम पानी और कम लागत वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। किसानों को पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, बकरी पालन और उद्यानिकी जैसी गतिविधियों से जोड़कर अतिरिक्त आय के स्रोत विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्रों को आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया, ताकि किसान नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित हों।सांसद संतोष पाण्डेय ने ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन और जल संरक्षण पर जोर देते हुए किसानों को बहुविध फसलें अपनाने की सलाह दी। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव ने कहा कि ग्राम पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों से आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हो रहा है और ग्रामीण आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

गांव-गांव तक पहुंचता विकास

राजनांदगांव की ग्राम पंचायतों में सड़क, भवन, खेल मैदान और अन्य अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार हो रहा है और जनसामान्य को इसका सीधा लाभ मिल रहा है।

किसानों के लिए नई दिशा

फसल विविधीकरण, बीज वितरण और आर्थिक सहायता जैसे कदम किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर नई संभावनाओं की ओर ले जा रहे हैं। कृषि के साथ पशुपालन और अन्य गतिविधियों को जोड़कर आय के नए स्रोत विकसित किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।

न्यूज रुटीन @ मोहला

12 जुलाई 2009... यह तारीख मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के इतिहास में कभी न भरने वाला जख्म बनकर दर्ज है। कोरकोट्टी के जंगलों में हुए नक्सली हमले में तत्कालीन एसपी विनोद चौबे समेत 29 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। उस दौर में इस पूरे इलाके की पहचान गोलियों की आवाज, बारूदी सुरंगों और खौफ से होती थी।

लेकिन 17 साल बाद तस्वीर बदल चुकी है।आज उसी इलाके में बंदूक उठाने की नहीं, वर्दी पहनने की होड़ दिखाई दे रही है। जिन गांवों में कभी सुरक्षाबलों के साथ खड़े होने से लोग डरते थे, वहां अब युवा सुबह-शाम मैदान में दौड़ लगाते नजर आते हैं। लक्ष्य सिर्फ एक—देश की वर्दी पहनकर सेवा करना।

ढाई साल...150 युवा...और बदलती सोच-पिछले करीब ढाई वर्षों में पुलिस और आईटीबीपी की संयुक्त पहल ने इलाके की दिशा बदलने का काम किया है। स्थानीय युवाओं को केंद्रीय सुरक्षा बलों, पुलिस और अन्य वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। करीब 150 युवाओं ने इस प्रशिक्षण का लाभ लिया, जिनमें से कई पैरामिलिट्री फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और पुलिस में चयनित भी हुए हैं। यह सिर्फ रोजगार की कहानी नहीं, बल्कि उस मानसिक बदलाव की मिसाल है जिसने हिंसा की जमीन पर उम्मीद के बीज बो दिए।

कोरकोट्टी की बरसी...अब सिर्फ शहादत नहीं, बदलाव का प्रतीक-कोरकोट्टी बलिदान दिवस अब केवल शहीदों को श्रद्धांजलि देने का अवसर नहीं रह गया है। यह उस परिवर्तन की भी गवाही देता है, जहां कभी भय का राज था, वहां अब विश्वास का माहौल है। जहां संघर्ष की पहचान थी, वहां अब विकास की चर्चा है। और जहां बंदूकों की गूंज थी, वहां आज भर्ती मैदानों में युवाओं के कदमों की आवाज सुनाई देती है।

सिर्फ सुरक्षा नहीं...विकास भी बना बदलाव की वजह-बदलाव केवल सुरक्षा मोर्चे पर नहीं हुआ, बल्कि विकास की रफ्तार ने भी वनांचल की तस्वीर बदल दी। नया जिला बनने के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 49.47 करोड़ रुपये की लागत से 310 किलोमीटर से अधिक लंबी 31 सड़क और पुल परियोजनाओं पर काम हुआ। इससे दूरस्थ आदिवासी गांव पहली बार सालभर सड़क संपर्क से जुड़े। जल संसाधन विभाग ने 36.88 करोड़ रुपये की 14 सिंचाई परियोजनाएं शुरू कीं, जिनसे करीब 2,600 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। वहीं लोक निर्माण विभाग 321.92 करोड़ रुपये की 29 सड़क और भवन परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जबकि सेतु विभाग ने 53.85 करोड़ रुपये की लागत से 15 बड़े पुलों को स्वीकृति दी, जिनमें अधिकांश पूरे हो चुके हैं।

स्वास्थ्य, बिजली और बैंकिंग भी पहुंची जंगलों तक-सुरक्षा के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी तेजी से हुआ है। सीजीएमएससी ने 56.82 करोड़ रुपये की लागत से 57 स्वास्थ्य अधोसंरचना परियोजनाएं शुरू कीं, जिनमें 53 पूरी हो चुकी हैं, जबकि 200 बिस्तरों वाला जिला अस्पताल निर्माणाधीन है। बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए 23 करोड़ रुपये की लागत से नए उपकेंद्र, ट्रांसफार्मर और विद्युत लाइन विस्तार किए गए। बैंकिंग सेवाओं में भी बड़ा बदलाव आया। जिले का क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात 26 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गया। बैंक शाखाओं की संख्या 30 से बढ़कर 35 हुई और 153 बैंक मित्रों के माध्यम से दूर-दराज के गांवों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचीं।

बदलाव की असली तस्वीर-कोरकोट्टी की शहादत ने इस क्षेत्र को दर्द दिया था, लेकिन उसी दर्द ने बदलाव की नींव भी रखी। आज मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की नई पहचान यह है कि यहां के युवा बंदूक की नली नहीं, बल्कि तिरंगे वाली वर्दी में अपना भविष्य देख रहे हैं। यह सिर्फ विकास की कहानी नहीं, बल्कि उस विश्वास की वापसी है जिसने कभी भय के साये में जी रहे वनांचल को नई दिशा दी है।

राम मंदिर चंदा चोरी पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज, बैज ने कहा- चौकीदार हैं तो कैसे हुई चोरी?

न्यूज रुटीन @ रायपुर

छत्तीसगढ़ में राम मंदिर के नाम पर एकत्र चंदे में हुई कथित चोरी ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

चौकीदार हैं तो चोरी कैसे हो गई: दीपक बैज-कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मामले में भाजपा पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के नेता खुद को देश का चौकीदार कहते हैं। यदि चौकीदार पहरा दे रहे थे, तो फिर चंदे की चोरी कैसे हो गई? उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में भाजपा के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस का मानना है कि इस चोरी में भाजपा के ही लोग शामिल हो सकते हैं।

सड़क से सदन तक गूंजेगा मुद्दा-कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि वे इस मामले को चुपचाप नहीं बैठने देंगे। पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक पूरी मजबूती से उठाएगी। कांग्रेस का दावा है कि चंदा राम मंदिर के नाम पर लिया गया था। इसलिए इसकी जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार जिला मुख्यालयों पर एकत्रित होकर भाजपा सरकार को घेर रहे हैं।

अपराधियों का अध्यक्ष वाले पोस्ट पर पलटवार-भाजपा ने बीते 12 जुलाई को सोशल मीडिया पर पीसीसी चीफ दीपक बैज के खिलाफ एक पोस्ट किया था। इसमें बैज को अपराधियों का अध्यक्ष बताया गया था। इस पर दीपक बैज ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्यकाल हमेशा संघर्षपूर्ण और जनहित के लिए रहा है। बैज ने भाजपा पर अपराधियों को पालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कोरिया, दुर्ग और तिल्दा की घटनाओं का जिक्र किया। बैज ने दावा किया कि इन सभी अपराधों में भाजपा से जुड़े लोग ही शामिल रहे हैं।

ई-20 पेट्रोल देश की जनता के लिए मुसीबत बना : दीपक बैज

न्यूज रुटीन @ रायपुर

एथेनाल मिश्रित पेट्रोल (ई-20) के कारण जनता परेशान हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ई-20 पेट्रोल देश की जनता के लिए मुसीबत बना। मोदी सरकार ने नफा नुकसान का वैज्ञानिक परीक्षण किये बिना पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनाल मिला कर पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया है जिसके कारण लोगों के वाहन खराब हो रहे है।

ई-20 पेट्रोल के कारण लोगों की गाड़ियां न सिर्फ खराब हो रही है इस एथेनाल वाले पेट्रोल के कारण वाहनों की माईलेज भी आधा हो गया है। मोदी सरकार ने अपने एक मंत्री की जिद और उनके पुत्रों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश को संकट में डाल दिया है। ई-20 पेट्रोल आम पेट्रोल की अपेक्षा शुरू नहीं है इसीलिए माईलेज में कमी आ रही है तथा गाड़ियों के इंजन भी खराब हो रहे है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विशेषज्ञों का कहना है ई-20 पेट्रोल के कारण एथेनाल हवा से नमी को जल्दी सोख लेता है। पुराने वाहनों में लगे मेटल (लोहे) के फ्यूल टैंक और फ्यूल पंप में इस नमी के कारण अंदर ही अंदर जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है, जो इंजन में जाकर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि एथेनाल एक बेहतरीन (घुलनशील) की तरह काम करता है। अप्रैल 2023 से पहले बनी (या केवल ई-10 के लिए डिजाइन की गई) गाड़ियों के रबर सील, गैस्कैट, प्लास्टिक और फ्यूल पाइप एथेनाल के संपर्क में आने से कमजोर होकर टूटने या रिसने लगते है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लंबे समय तक ई-10 या उससे कम क्षमता के लिए बनी गाड़ियों में सीधे ई-20 ईंधन डालने से फ्यूल इंजेक्टर जाम हो सकते है और महंगे पुर्जे खराब हो सकते है, जिससे भारी मेंटेनेंस खर्च उठाना पड़ सकता है।

शराब में ढाई साल में 3870 करोड़ का ओवर रेटिंग घोटाला हो गया है - कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश में शराब धड़ल्ले से ओवर रेट में बेची जा रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस पूरे खेल को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। शराब की ओवर रेटिंग सरकार में बैठे हुए लोग करा रहे है। हर ब्रांड की शराब में 10 से 60 रू. तक प्रति बोतल वसूला जा रहा था। शराब के काऊंटर में बैठे लोग दावा कर रहे है कि शराब का पैसा ऊपर तक जा रहा था। यह मामला मीडिया मे आया और जनता ने विरोध किया तब जाकर कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करने की कार्यवाही की गयी। अधिकारी तो सरकार के निर्देश पर काम कर रहे थे उन्हे बलि का बकरा बना दिया गया। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकारी आंकड़ों में प्रतिदिन शराब का विक्रय 28 लाख 65 हजार बोतल है, हर बोतल में 10 से 60 रू. अधिक वसूला जा रहा है, 4 करोड़ 29 लाख प्रतिदिन अवैध वसूली, महिनें का 129 करोड़, 1548 करोड़ सालाना.

अमेरिका-ईरान टकराव और विश्व शांति की नई चुनौती

ललित गर्ग

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे तनाव के बाद बड़ी कठिनाई से बना संघर्ष विराम अपनी निर्धारित अवधि पूरी करने से पहले ही टूटने की कगार पर पहुंच गया है। ईरान द्वारा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए ताजा हमलों और उसके जवाब में अमेरिका की भीषण बमबारी ने एक बार फिर पूरी दुनिया को युद्ध की आशंकाओं के बीच खड़ा कर दिया है। यह केवल दो देशों के बीच का सैन्य संघर्ष नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति, आर्थिक स्थिरता और मानवीय मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती है। जिस समय विश्व को महामारी, आर्थिक मंदी, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट जैसी समस्याओं से मिलकर लड़ना चाहिए, उस समय महाशक्तियों का युद्धोन्माद पूरी मानवता को पीछे धकेलने का कार्य कर रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर उत्पन्न विवाद ने इस संघर्ष को और अधिक विस्फोटक बना दिया है। विश्व के लगभग 20 प्रतिशत कच्चे तेल की आपूर्ति इसी समुद्री मार्ग से होती है। यदि यह मार्ग बाधित होता है तो केवल तेल की कीमतें ही नहीं बढ़ेंगी, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक दुष्प्रभाव पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, उत्पादन लागत में वृद्धि होगी, आपूर्ति श्रृंखलाएं टूटेंगी और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक प्रभावित होगी। युद्ध की आग कभी सीमाओं में नहीं रहती, उसकी तपिश अंततः पूरी दुनिया को झुलसाती है।

इस संघर्ष का सबसे दुखद पक्ष यह है कि इसमें निर्दोष नागरिकों, नाविकों और आम जनजीवन को सबसे अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। हाल के घटनाक्रम में भारतीय नाविकों के प्रभावित होने और भारत के सहयोग से विकसित रणनीतिक महत्व वाले चाबहार बंदरगाह परियोजना को नुकसान पहुंचने से यह स्पष्ट हो गया है कि युद्ध किसी एक देश तक सीमित नहीं रहता। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक विश्वास-तीनों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अमेरिका स्वयं को लोकतंत्र और विश्व व्यवस्था का संरक्षक बताता है, लेकिन उसकी विदेश नीति लंबे समय से प्रतिबंधों, सैन्य दबाव और शक्ति प्रदर्शन पर आधारित रही है। किसी भी राष्ट्र को झुकाने के लिए आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य हमले और राजनीतिक दबाव स्थायी समाधान नहीं हो सकते। महाशक्ति होने का अर्थ केवल सैन्य सामर्थ्य नहीं, बल्कि संयम, दूरदृष्टि और विश्व समुदाय के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व भी है। यदि शक्ति विवेक से संचालित न हो तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। दूसरी ओर ईरान को भी यह समझना होगा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों को अपने रणनीतिक हितों के लिए बंधक बनाना न तो अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप है और न ही वैश्विक विश्वास के अनुकूल। किसी भी देश की सुरक्षा तब तक स्थायी नहीं हो सकती जब तक वह पड़ोसी देशों और विश्व समुदाय के साथ सहयोग, विश्वास और पारदर्शिता का वातावरण निर्मित न करे। भय और प्रतिशोध पर आधारित सुरक्षा व्यवस्था अंततः स्वयं को ही असुरक्षित बना देती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली ने इस पूरे संकट को और अधिक अनिश्चित बनाया है। एक ओर वे कठोर सैन्य कार्रवाई करते हैं, दूसरी ओर वार्ता और समझौते की बातें करते हैं। इस प्रकार के विरोधाभासी संदेश न केवल कूटनीतिक विश्वास को कमजोर करते हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अस्थिरता पैदा करते हैं। महाशक्तियों के नेताओं के प्रत्येक वक्तव्य का प्रभाव केवल उनके देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था, निवेश, ऊर्जा बाजार और करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ता है। इसलिए नेतृत्व में धैर्य, स्थिरता और विश्वसनीयता अत्यंत आवश्यक है। इतिहास गवाह है कि युद्धों ने कभी स्थायी समाधान नहीं दिया। प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध से लेकर इराक, अफगानिस्तान, लीबिया और सीरिया तक, हर युद्ध ने नई समस्याएं ही पैदा की हैं। लाखों लोगों की जान गई, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, लेकिन अंततः समाधान फिर बातचीत की मेज पर ही खोजे गए। यदि अंत में संवाद ही करना है, तो शुरुआत भी संवाद से ही क्यों नहीं हो सकती? यही प्रश्न आज पूरी मानवता के सामने खड़ा है। भारत ने सदैव विश्व को शांति, सह-अस्तित्व और अहिंसा का मार्ग दिखाया है। गौतम बुद्ध, भगवान महावीर और महात्मा गांधी की भूमि ने यह सिखाया कि वास्तविक विजय शत्रु को पराजित करने में नहीं, बल्कि शत्रुता को समाप्त करने में है। भारत की विदेश नीति भी 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और 'विश्वबंधुत्व' के आदर्शों पर आधारित रही है। भारत ने हमेशा संवाद, कूटनीति और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। यही कारण है कि भारत आज विश्वसनीय मध्यस्थ, संतुलित शक्ति और जिम्मेदार वैश्विक भागीदार के रूप में सम्मान प्राप्त कर रहा है। वर्तमान संकट में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत के अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों के साथ संतुलित संबंध हैं। भारत यदि संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों के माध्यम से सक्रिय शांति पहल करे, तो तनाव कम करने में उसकी भूमिका प्रभावी सिद्ध हो सकती है। साथ ही भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी दूरदर्शी रणनीति अपनानी होगी। आज आवश्यकता किसी एक पक्ष की विजय की नहीं, बल्कि मानवता की विजय की है। हथियारों की होड़ से न तो समृद्धि आती है और न ही सम्मान। वास्तविक शक्ति मिसाइलों, बमों और युद्धपोतों में नहीं, बल्कि विश्वास, सहयोग और संवाद में निहित होती है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, वह केवल नई समस्याओं को जन्म देता है। अहिंसा कायरता नहीं, बल्कि आत्मबल, धैर्य और दूरदर्शिता का सर्वोच्च स्वरूप है।

विश्व समुदाय को अब यह स्पष्ट संदेश देना होगा कि किसी भी देश की मनमानी, सामरिक अहंकार और युद्धोन्माद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र सहित वैश्विक संस्थाओं को अधिक प्रभावी, निष्पक्ष और सक्रिय भूमिका निभानी होगी। यदि आज भी दुनिया ने युद्ध की राजनीति पर अंकुश नहीं लगाया, तो भविष्य की पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी। आज पूरी दुनिया की प्रार्थना यही है कि अमेरिका को शक्ति के साथ सद्बुद्धि मिले, ईरान को संयम और विवेक का मार्ग मिले तथा दोनों राष्ट्र हथियारों की भाषा छोड़कर संवाद की संस्कृति अपनाएं। शांति ही विकास का आधार है, संवाद ही स्थायी समाधान का मार्ग है और अहिंसा ही मानव सभ्यता का सबसे बड़ा अस्त्र है। यही समय की पुकार है, यही मानवता की अपेक्षा है और यही भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता भी।

रामलला के पैसे की चोरीः आस्था पर घात, डगमगाया विश्वास

अजय कुमार,

अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर से दान पात्र में चोरी की घटना ने एक साथ कई मोर्चों पर हलचल मचा दी है। करोड़ों रामभक्तों की आस्था को इस घटना ने गहरी ठेस पहुँचाई है तो उनका यह विश्वास भी टूट गया कि रामलला के मंदिर में ऐसा कुछ कभी हो ही नहीं सकता है, लेकिन इससे भी बड़ी चोट तब लगी, जब इस धार्मिक मसले को राजनीति की चाशनी में लपेटकर परोसा जाने लगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को हाथों-हाथ लपक लिया और भारतीय जनता पार्टी की हिन्दूवादी राजनीति पर निशाना साधने में ज़रा भी देर नहीं की। यह सवाल अपनी जगह वाजिब है कि जिस मंदिर के दर्शन के लिये अखिलेश यादव आज तक नहीं गये, उस मंदिर के दान पात्र से हुई चोरी पर उनकी तड़प और चिंता कितनी वास्तविक है और कितनी दिखावटी। जो नेता रामलला के दर्शन से परहेज़ करते रहे, वे अचानक मंदिर की सुरक्षा और प्रबंधन के पहरेदार बन बैठे हैं। इसमें सच्चाई कम, सियासी गणित ज़्यादा दिखता है। सपा की इस सियासत से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिये 19 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या रामलला के मंदिर पहुँच रहे हैं, जहाँ वह पूरे घटनाक्रम को बारीकी से समझेंगे।उधर, अखिलेश यादव की मंशा साफ है। वे भाजपा की हिन्दुत्व की छवि को खंड-खंड करना चाहते हैं। भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया था। यह मंदिर केवल ईंट-पत्थर का ढाँचा नहीं, बल्कि भाजपा की राजनीतिक पहचान का आधार-स्तंभ है। जब उसी मंदिर में चोरी होती है, तो यह भाजपा के लिये केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि उसकी हिन्दुत्व की साख पर सीधा प्रहार बन जाता है। अखिलेश यादव इस कमजोर कड़ी को पकड़कर हिन्दू मतदाताओं के मन में यह संदेश डालना चाहते हैं कि भाजपा का हिन्दुत्व केवल चुनावी नारा है, व्यवहार में नहीं। इसके पीछे एक और सोचा-समझा राजनीतिक लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में हिन्दू मतदाता कभी एकजुट नहीं रहे। उच्च जातियों, पिछड़े वर्गों और दलितों के बीच की खाई को समाजवादी पार्टी हमेशा अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करती रही है। यदि अखिलेश इस घटना के माध्यम से हिन्दुओं के किसी तबके में यह धारणा बनाने में सफल हो जाते हैं कि भाजपा की सरकार में राम के घर में भी सुरक्षा नहीं, तो यह उनके लिये 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक फायदा होगा।

लेकिन इस पूरे प्रसंग में असली सवाल यह है कि यह नौबत आई क्यों? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय की भूमिका यहाँ बेहद अहम है। यदि वे इस घटना की जानकारी मिलते ही इसका खुलासा सार्वजनिक रूप से कर देते और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की बात करते, तो विपक्ष के पास आरोप लगाने की गुंजाइश ही नहीं बचती। जो घटना खुद उजागर की जाये, उस पर राजनीति करना कठिन होता है। लेकिन जब घटना को दबाने की कोशिश होती है और बाद में वह बाहर आती है, तो वह कहीं अधिक विस्फोटक बन जाती है। चंपत राय की यह अदूरदर्शिता महँगी पड़ी। इसी चूक ने अखिलेश को एक ऐसा हथियार थमा दिया, जिसे वे बार-बार भाँज सकते हैं। सपा की मंशा को भाँपकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए विशेष जांच दल का गठन किया है। यह कदम ज़रूरी था, लेकिन राजनीतिक नुकसान तो हो चुका था। जब तक जांच का आदेश आया, तब तक यह मुद्दा सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर आग की तरह फैल चुका था। मोदी और योगी दोनों की सरकारें इस मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में दिखीं, जो आमतौर पर सत्ता पक्ष के लिये ठीक संकेत नहीं माना जाता।

उधर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बयानबाज़ी में भी अतिरंजना है। वे ऐसी बातें भी इस घटना से जोड़ रहे हैं, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में यह स्वाभाविक भी है, लेकिन इससे उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। जो नेता कभी मंदिर के दर्शन नहीं करते, उनका मंदिर प्रेम अचानक चुनावी मौसम में जागता दिखे, तो जनता उसे पहचानती है। लाख टके का सवाल यह भी है कि यह मुद्दा क्या 2027 तक जीवित रह सकता है? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार और राम जन्मभूमि न्यास इसे किस तरह संभालते हैं। यदि जांच में देरी हुई, दोषी पकड़ में नहीं आये, या मंदिर प्रशासन में कोई बड़ी खामी सामने आई, तो अखिलेश इसे ज़िंदा रखने में सफल होंगे। लेकिन यदि शीघ्र कार्रवाई हुई, दोषियों को सजा मिली और मंदिर प्रशासन में सुधार दिखा, तो यह मसला अपने आप ठंडा पड़ जायेगा। राजनीति में वही मुद्दे टिकते हैं, जिन्हें सत्ता पक्ष की लापरवाही ताज़ा रखती है।

लब्बोलुआब यह है कि रामलला का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था का केन्द्र है। इस मंदिर से जुड़ी हर घटना, चाहे वह चोरी हो या कोई और विवाद, स्वाभाविक रूप से राजनीतिक रंग ले लेती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस मंदिर के निर्माण से लाखों लोगों की भावनाएँ जुड़ी हैं, वह अब राजनीतिक शतरंज की बिसात बन रहा है। अखिलेश यादव इस बिसात पर चाल चल रहे हैं और भाजपा खुद की भूलों के कारण मुश्किल स्थिति में है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि राम मंदिर प्रबंधन को पारदर्शी और चुस्त-दुरुस्त बनाया जाये। चोरी की घटना से जो सबक मिला है, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिये। मंदिर की सुरक्षा और प्रशासन में खामियाँ न केवल आस्था को आहत करती हैं, बल्कि विरोधियों को राजनीति करने का अवसर भी देती हैं। आस्था की रक्षा और प्रशासन की पारदर्शिता ही वह ढाल है, जो सियासत के तीरों को बेअसर कर सकती है।

महतारी वंदन योजना बनी महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की नई पहचान

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित महतारी वंदन योजना हजारों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालित इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत नियमित रूप से मिल रही आर्थिक सहायता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास को भी नई मजबूती प्रदान कर रही है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के विकासखंड गौरेला के ग्राम पंचायत डुमरिया की श्रीमती बसंती धुर्वे इसका प्रेरणादायक उदाहरण है।

श्रीमती बसंती धुर्वे ने बताया कि उन्हें महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त की राशि उनके बैंक खाते में प्राप्त हो गई है। इस राशि से उन्हें दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, घरेलू खर्चों के बेहतर प्रबंधन तथा परिवार की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नियमित आर्थिक सहायता मिलने से अब वे अधिक आत्मविश्वास के साथ परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में सहभागी बन रही हैं। श्रीमती बसंती धुर्वे का कहना है कि महतारी वंदन योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को सम्मान, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर भी प्रदान कर रही है। योजना से मिलने वाली राशि महिलाओं को छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से मुक्त कर रही है तथा उन्हें परिवार के निर्णयों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिल रहा है।उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऐसी जनकल्याणकारी योजना लागू की है, जिसका लाभ सीधे महिलाओं तक पहुंच रहा है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ उनके जीवन में आत्मविश्वास, सुरक्षा और सम्मान की भावना भी विकसित कर रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन के कारण महतारी वंदन योजना का लाभ प्रदेशभर की लाखों महिलाओं तक नियमित रूप से पहुंच रहा है। योजना महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने, परिवारों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने तथा समावेशी विकास के राज्य सरकार के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

महतारी वंदन योजना आज प्रदेश की महिलाओं के लिए केवल एक आर्थिक सहायता ही नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और उनके जीवन स्तर में सतत सुधार लाने की दिशा में निरंतर प्रभावी कार्य कर रही है।

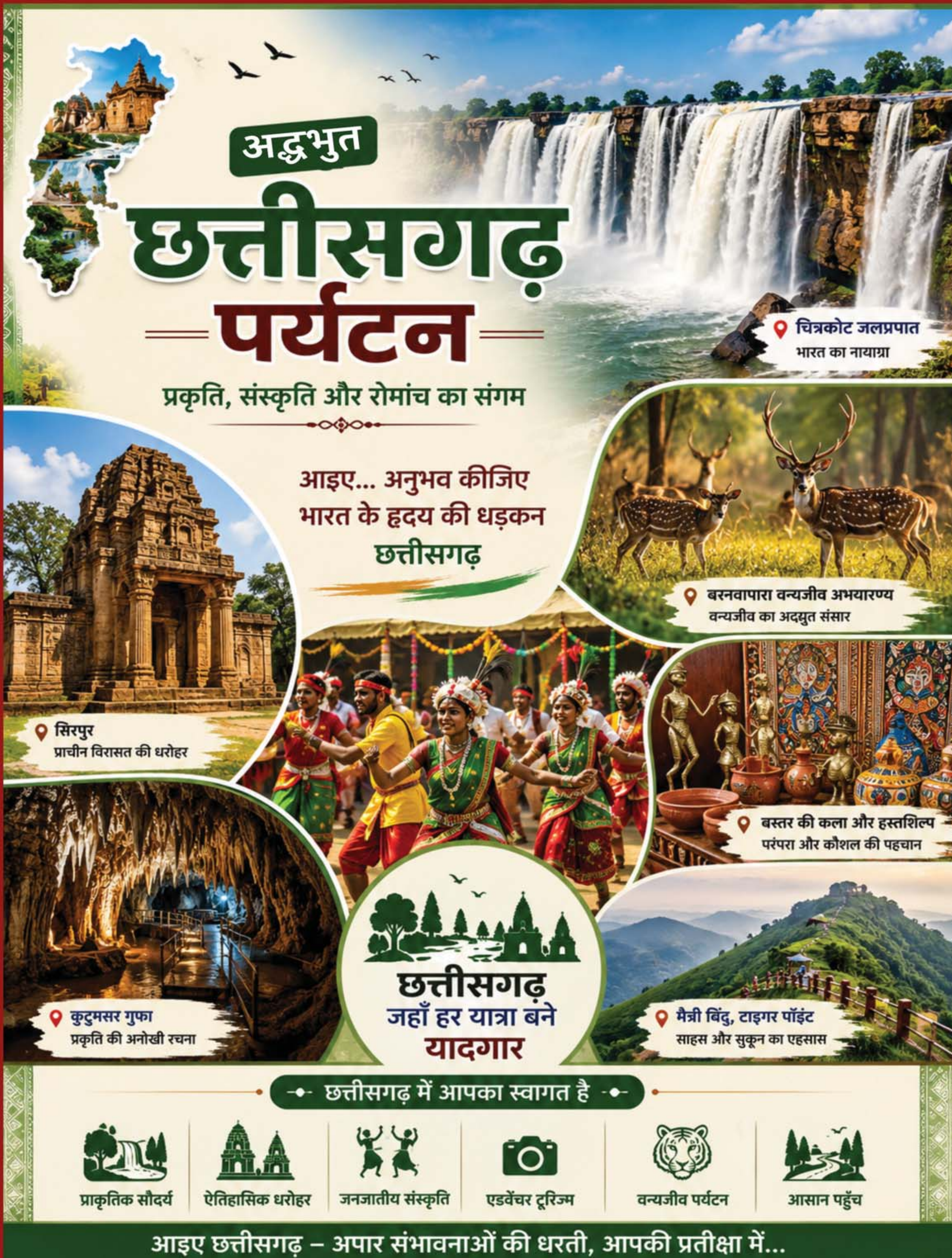

अद्भुत
छत्तीसगढ़
पर्यटन
प्रकृति, संस्कृति और रोमांच का संगम
चित्रकोट जलप्रपात
भारत का नायाग्रा
आइए... अनुभव कीजिए
भारत के हृदय की धड़कन
छत्तीसगढ़
बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य
वन्यजीव का अद्भुत संसार
सिरपुर
प्राचीन विरासत की धरोहर
बस्तर की कला और हस्तशिल्प
परंपरा और कौशल की पहचान
कुटुमसर गुफा
प्रकृति की अनोखी रचना
छत्तीसगढ़
जहाँ हर यात्रा बने
यादगार
मैत्री बिंदु, टाइगर पॉइंट
साहस और सुकून का एहसास
छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है
प्राकृतिक सौंदर्य
ऐतिहासिक धरोहर
जनजातीय संस्कृति
एडवेंचर टूरिज्म
वन्यजीव पर्यटन
आसान पहुँच
आइए छत्तीसगढ़ – अपार संभावनाओं की धरती, आपकी प्रतीक्षा में...